सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

06 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 06 फरवरी, 2026 ई॰
द्वितीय सत्र — 17 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना पर खड़ा हूं । आज सुबह कई माननीय सदस्य आये थे जीरो आवर का क्वैश्चन डालने के लिए, पोटिको में खड़े थे इतना बड़ा–बड़ा मलवा ऊपर से गिरा और कई माननीय सदस्य बच गये, उसको दिखवा लेना उचित है महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, उसको निश्चित तौर पर दिखवा लेते हैं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम कार्य स्थगन दिये हुए हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–3, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या–75, सहरसा)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2023 में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है वह National Health Estimates, 2019-2020 के आधार पर है, जिसमें Government Health Expenditure 8,477/–(आठ हजार चार सौ सतहत्तर) करोड़ रू0 दर्शाया गया है जो कि बढ़कर वर्ष 2024–25 में 15488.01/–(पन्द्रह हजार चार सौ अठासी करोड़ एक लाख) करोड़ रू0 हो गया है।

इस प्रकार खर्च में कुल 7011/–(सात हजार ग्यारह) करोड़ रू0 की वृद्धि हुई है। विदित हो कि वर्ष 2019–20 में दवा मद में कुल–215.24 (दो सौ पन्द्रह करोड़ चौबीस लाख) करोड़ रू0 खर्च किये गये थे, जो कि वर्ष 2024–25 में बढ़कर 758/–(सात सौ अन्ठावन) करोड़ रू0 हो गया है। इस प्रकार दवा में बिहार सरकार का खर्च वर्ष 2019–20 की अपेक्षा तीन गुणा से ज्यादा बढ़ा है।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2023 के प्रकाशित आंकड़ों में यह उल्लेखित है कि बिहार का Government Health Expenditure, GSDP का 1.5 प्रतिशत है, जबकि झारखण्ड का 1.2 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल का 1.1 प्रतिशत है।

बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट–3 में प्रखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र एवं जिला अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। 7 निश्चय पार्ट–3 के तहत् प्रखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कान नाक एवं गला रोग के विशेषज्ञों के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। साथ ही जिला अस्पतालों में Endocrinology, Cardiology, Urology एवं Neurology विधा के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

उपर्युक्त गतिविधियों से राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जवाब मांगा था कि बिहार में हैल्थ पर कितना पर–कैपिटा खर्च किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं लेकिन अभी तक जवाब अप्राप्त है महोदय । बिहार में हमारे पास जो जानकारी अवलेवल है कि हैल्थ केयर पर एक हजार से पर–कैपिटा खर्च किया जाता है पर ए0एन0एम0 और बिहार इस मामले में सबसे नीचे है महोदय। जब–जब यह स्थिति पैदा होती है, आई0एम0आर0 जो है बिहार का इन्फेंट मोर्टेनिटी रेट बहुत बढ़ता है महोदय । आप देखेंगे कि हरेक पी0एच0सी0 में लगभग 500 महिलाएं प्रसव पीड़ा से आती हैं और उनमें 90 प्रतिशत महिला लगभग 450 महिलाएं एनिमिक होती हैं और यह लीड करता है कि जो बच्चे की मृत्यु दर है बिहार में सबसे ज्यादा होती है । आप देखेंगे कि इसकी वजह से पॉपुलेशन टू बेड है उसकी संख्या बहुत कम है, एक लाख में मात्र 37 बेड है बिहार में और डॉक्टरों की संख्या 21 है एक लाख में ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं वही ले रहा हूं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार आखिर इस पर क्या कर रही है । आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है नागरिकों का वह बहुत बढ़ता है और जब–जब एक हजार से कम होता है मात्र 701 रुपया है, जब–जब यह स्थिति आती है यह बोर्ड स्टेट फेल करता है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है और यही एक वजह है कि पेसेंट वहां जो हमलोग करते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी, इसकी भारी कमी होती है । आप किशनगंज में जाइये 40 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट सेंक्संड हैं और उसमें मात्र 20 भरे हुए हैं । सरकार इसमें क्या कर रही है हम यह जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2023 में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है वह National Health Estimates, 2019-2020 के आधार पर है, जिसमें Government Health Expenditure 8,477/–(आठ हजार चार सौ सतहत्तर) करोड़ रू0 दर्शाया गया है जो कि बढ़कर वर्ष 2024–25 में 15488.01/–(पन्द्रह हजार चार सौ अठासी करोड़ एक लाख) करोड़ रू0 हो गया है।

इस प्रकार खर्च में कुल 7011/–(सात हजार ग्यारह) करोड़ रू0 की वृद्धि हुई है। विदित हो कि वर्ष 2019–20 में दवा मद में कुल–215.24 (दो सौ पन्द्रह करोड़ चौबीस लाख) करोड़ रू0 खर्च किये गये थे, जो कि वर्ष 2024–25 में बढ़कर 758/–(सात सौ अन्ठावन) करोड़ रू0 हो गया है। इस प्रकार दवा में बिहार सरकार का खर्च वर्ष 2019–20 की अपेक्षा तीन गुणा से ज्यादा बढ़ा है।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2023 के प्रकाशित आंकड़ों में यह उल्लेखित है कि बिहार का Government Health Expenditure, GSDP का 1.5 प्रतिशत है, जबकि झारखण्ड का 1.2 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल का 1.1 प्रतिशत है।

बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट–3 में प्रखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र एवं जिला अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। 7 निश्चय पार्ट–3 के तहत् प्रखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कान नाक एवं गला रोग के विशेषज्ञों के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। साथ ही जिला अस्पतालों में Endocrinology, Cardiology, Urology एवं Neurology विधा के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

उपर्युक्त गतिविधियों से राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय को पता होना चाहिए कि भारत सरकार भी 6,000 रुपया मातृ वंदना के तहत.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप यह माननीय सदस्य को बताइये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है कि....

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : उस अनुपात में बढ़ा है....

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो चीज मैंने सरकार से पूछा है, सरकार को यह बात समझ में नहीं आयी ।

अध्यक्ष : प्रमोद जी, बैठ जाइये, माननीय सदस्य की बात सुन लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यह मानक होता है कि आपके विश्व बैंक में या आपके हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रोफाइल नागरिकों का क्या है । माननीय मंत्री जी, ठीक उसी तरह का बता रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 19 मरीज आता था, अब 11 हजार 600 कुछ आ रहा है । आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार ने आपको कहा है लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब पर कैपिटा इनकम, यही मानक होता है, हेल्थ प्रोफाइल और हेल्थ स्टेटस का और आप बता रहे हैं कि आपने क्या–क्या किया । अगर आप यह करते तो आज यह हालत नहीं होती, आज आपको पता है कि जब डॉक्टर हमारे यहां नहीं हैं यह सिर्फ पर–कैपिटा जब एक्सपेंडिचर 1000 से कम होता तो ये सारी सिचुएशन होती है, हम वहां पर डॉक्टरों को दोष दे रहे हैं कि रेफर कर देता है । यह जो ए0ओ0पी0 की बात मैं कह रहा हूं जब आप अस्पताल में जाते हैं और वहां सुविधा नहीं होती है तो तुरंत रेफर करते हैं पटना और ये जो एम्बुलेंस वाले पेसेंट को भेज देता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और यह.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गुप्ता जी ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : यह डेथ को बढ़ाता है, हमलोग गरीबी में डूबते चले जाते हैं इसकी वजह से ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं सरकार ने जो डाटा अभी दिया है, यह बताने में ये बिल्कुल असक्षम हो रहे हैं कि पर–कैपिटा खर्च कितना होगा और यह कब तक बढ़ेगा हम यह जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप माननीय सदस्य को अलग से कॉपी उपलब्ध करवा दीजिएगा, अगर अभी आपके पास नहीं है तो ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, सही बात है कि माननीय मंत्री ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया है । इन्होंने आई0एम0आर0 की बात कही, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेश्यो की बात कही तो मंत्री जी ने बताया है कि हमलोगों ने जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों के लिए बढ़ायी हैं उससे न सिर्फ आई0एम0आर0 जिसकी चर्चा कर रहे थे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेश्यो, एम0एम0आर0 भी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेश्यो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है । जो आप आई0एम0आर0 की बात कहे थे...

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए । पहले 40 इन्फेंट प्रति हजार डिलीवरी से अधिक हुआ करता था और सरकार ने जब सुविधाएं बढ़ायी हैं तो आई0एम0आर0 अब घटकर 22–23 पर आ गया

है और जो चीज आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की बात कही, मंत्री जी ने तो स्पष्ट बता दिया है कि हमारा जो जी0एस0डी0पी0 है, पूरे स्टेट का जो खर्चा है उसमें जो हम आम लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं वह 1.5 प्रतिशत है जो आप झारखंड या किस–किस से तुलना किये हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने कर दी, उनलोगों से अधिक हम जो जी0एस0डी0पी0 का खर्चा आम लोगों के स्वास्थ्य पर करते हैं इसलिए महोदय जो माननीय सदस्य की चिंता थी, सरकार उस पर पूरी तरह सजग है और सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है और स्वास्थ्य के हर पैरामीटर पर यानी हर मापदंड पर हमलोग लगातार सुधार कर रहे हैं, यह हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माधव आनंद ।

उत्तर बहुत स्पष्ट हो गया है । प्लीज बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : संकट कारक हैं क्या ?

टर्न–2 / सुरज / 06.02.2026

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–4, श्रीमती स्नेहलता (क्षेत्र संख्या–208, सासाराम)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माधव आनंद को प्राधिकृत किया गया है । उत्तर आया है न ?

श्री माधव आनंद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, पूछ लीजिये ।

श्री माधव आनंद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं क्या, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आशा कार्यकर्ता प्रसव और अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रात–दिन अस्पतालों में मौजूद रहती हैं, किन्तु सासाराम सहित राज्य के अधिकांश प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य ...

अध्यक्ष : उत्तर सुन लीजिये पहले । माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में रोहतास (सासाराम) जिलान्तर्गत 01 जिला अस्पताल (रोहतास) में, 02 अनुमण्डलीय अस्पताल (डेहरी ऑनसोन एवं बिक्रमगंज) में एवं 02 रेफरल अस्पताल (नासरीगंज एवं नवहट्टा) में आशा घर क्रियाशील है। साथ ही राज्य के 91 स्वास्थ्य संस्थानों यथा–जिला अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पताल में भी आशा घर क्रियाशील है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त आशा घर के निर्माण हेतु कार्रवाई की जायेगी।

श्री माधव आनंद : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–5, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या–193, बड़हरा)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : केन्द्र सरकार अन्तर्गत कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत प्रदान की जाती है ।

वस्तुस्थिति यह है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कर्मियों तथा पेंशनर्स के लिये कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना'' लागू किया गया हैं। साथ ही झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य तथा राज्य के सभी कार्यरत/सेवानिवृत कर्मियों एवं उनके आश्रितों हेतु एक निश्चित राशि तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया गया है।

वर्तमान में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–228(14) दिनांक 25.02.2008 संकल्प सं0–946(14) दिनांक 14.8.2015 एवं समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग से निर्गत विभिन्न संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य एवं उनके आश्रितों द्वारा राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति प्रावधानानुसार किया जाता है। साथ ही राज्य के सभी सेवारत कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदत्त है।

बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य एवं राज्य के सभी कार्यरत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मियों एवं उनके आश्रितों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा प्रश्न है मैं समझता हूं कि. ..

अध्यक्ष : उत्तर मिल गया है न ?

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : जी, उत्तर मिल गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : इसमें आश्वासन दिया गया है माननीय मंत्री जी की तरफ से कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है । यह बात जो आज मैंने इस प्रश्न में रखा है, जितने सदस्य हम आज यहां बैठे हुए हैं और जो लोग भी कार्यरत हैं राज्य सचिवालय में या अन्य जगहों पर । हमारे बगल के राज्यों ने कैशलेस सुविधा दे दी है । उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, और केन्द्र में भी है । दिक्कत यह है कि अभी जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं । हम जांच कराते हैं तो वहां बहुत सी जगहों पर रशीद नहीं ले पाते हैं या कोई प्रूफ नहीं रहता है और हम जो देते

हैं उसके बाद उसकी जांच की जाती है । कोई मरीज हम हों या इसमें जितने लोगों को शामिल किया गया है वह अस्पताल में जाएं, दम तोड़ दें उसके बाद कोई सुविधा मिले इसका तो कोई तात्पर्य नहीं होता है और मैं, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं इन्होंने कैशलेस सुविधा की बात कही थी और जहां तक मुझे जानकारी मिली है जब ये रेलवे मंत्री थे तो इन्होंने कैशलेस सुविधा भी देने का काम वहां पर किया था । तो आज इससे वंचित क्यों किया जा रहा है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां नहीं हैं, प्रभार में हैं वह अपनी बात पूरी नहीं रख पायेंगे, मैं जानता हूं इसलिये आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार करके और सरकार से कहें कि इस पर फैसला तत्काल ले लिया जाए । विचाराधीन है, क्या विचाराधीन है । यह कई वर्षों से विचाराधीन है, कब तक सरकार इस पर विचार करेगी । यह तो होना चाहिये न । जितने सदस्य यहां बैठे हुए हैं...

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है, पूरी तरह सरकार सहमत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है, इसको करना है । मैं सहमत हूं सी0जी0एच0एस0 में यदि सबकी सहमति होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है । लेकिन जो सुविधा अभी हम दे रहे हैं, उससे अच्छा सी0जी0एच0एस0 की सुविधा नहीं है, यह मैं बता रहा हूं । मैं तो चाहूंगा, आपलोगों का भी सहयोग मिले । मैंने तीन बैठक इसके लिए विशेष तौर पर किया है और आगे भी मैं चाहता हूं कि अच्छा सुझाव हमको मिले । मैं पूर्ण रूप से सी0जी0एच0एस0 की मांग यदि करते हैं तो मैं तुरंत सहमत हूं कल सरकार निर्णय ले लेगी । लेकिन कैशलेस की ही बात उससे अच्छी सुविधा हम दे रहे हैं । हम कैशलेस से अधिक अच्छा सुविधा दे रहे हैं । एक प्रॉब्लम जरूर आता है कि एडवांस में हमको पैसा देना पड़ता है तो राज्य सरकार ने यह व्यवस्था किया है कि आपके माध्यम से हम एडवांस पैसा भी देते हैं । लेकिन अच्छा सुझाव आया मैं जरूर माननीय सदस्य और कई वरिष्ठ साथियों से आग्रह करूंगा कि सुझाव दीजिये, इसको सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको करेगी ।

अध्यक्ष : इसकी एक बैठक बुलवा लीजिये ।

(व्यवधान)

हमार सुझाव होगा कि माननीय मंत्री जी एक सप्ताह के अंदर बैठक बुला लीजिये और बैठक बुलाकर आप सब लोगों की राय ले ली जाएगी ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, देखा जाए सीधी बात है कैशलेस । उसके अलावे हम कोई डिमांड आपसे नहीं कर रहे हैं और बगल के राज्यों में किया गया है और हमारी सरकार जो है वह कई तरह की सुविधाएं लोगों को दे रही है और

आपलोग भी दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं । लेकिन यह जो आप कहीं न कहीं घुमाने की बात कर रहे हैं...

अध्यक्ष : सरकार तैयार है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : इसको नहीं घुमाया जाए । इस पर स्पष्ट रूप से सरकार कहे कि हाँ कैशलेस की व्यवस्था सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : सरकार एक सप्ताह के अंदर में बैठक बुला करके, आप सदस्यों को बुला कर के..

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, आपसे उम्मीद है । अब आप बैठक की बात कह रहे हैं, ठीक है बैठक हो जाए । कई बैठकें हो चुकी, कई विचार हो चुके...

अध्यक्ष : यह अंतिम बैठक रहेगा ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : सीधी बात है कैशलेस ।

अध्यक्ष : यह अंतिम बैठक रहेगा, रिजल्ट आ जायेगा ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : राघवेन्द्र प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, अकेले राघवेन्द्र प्रताप सिंह सारे लोगों के लिये लड़ रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । सरकार माननीय विधायकों की राय से सहमत है । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है विश्वास कीजिये एक सप्ताह के अंदर बैठक बुलाकर, आप सबों से राय लेकर जो चाहत है वह कर दिया जायेगा ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं क्या इसमें है ।

अध्यक्ष : हो जायेग, थोड़ा धैर्य रखिये हो जायेगा ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली एम्स के कैश रिसिप्ट के ऊपर भी दिल्ली एम्स के एम0डी0 का सिग्नेचर मानने के बाद विधान सभा उसको रिइंबर्समेंट के लिए वेरिफाई करती है । दिल्ली एम्स का एम0डी0 मिलता है क्या और दिल्ली एम्स का कैश रिसिप्ट रहने के बाद रिइंबर्समेंट नहीं करती है और सदस्यों को परेशान किया जाता है । तो उसमें समय क्या लेना है ।

अध्यक्ष : धैर्य रखिये मिश्रा जी ।

श्री जिवेश कुमार : सरकार यहां है, सरकार उत्तर दे, इस पर समय क्या लेना है । कैशलेस में बेईमानी कहां है हुजूर ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये प्लीज । आप सबों की राय आ गयी है । थोड़ा सा...

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, एक चीज स्पष्ट है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बिना अनुमति के भाई वीरेन्द्र, बैठ जाइये प्लीज ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । सरकार खड़ी है जवाब देने के लिये, सुन लीजिये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, पूरी तरह सहमत हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिये, आपकी बात सुन लिया गया है । माननीय मंत्री जी खड़े हैं, सुन लीजिये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : पूरी तरह सहमत हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आग्रह है बैठ जाइये । आप वरीय सदस्य हैं, बैठ जाइये प्लीज । माननीय मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्यों की भावना से पूरी तरह सरकार सहमत है । मैंने दो ही चीज कहा । कई राज्यों में इसको इंश्योरेंस मोड में लोगों ने किया है । वह इंश्योरेंस मोड में करते हैं । हमारे यहां कृषि के ऊपर हमलोगों ने इंश्योरेंस मोड में किया था । हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा था तो इस पर ऑबजेक्शन्स क्रियेट हुए थे । लेकिन हम स्पष्ट हैं, हम पूरी तरह सहमत हैं । यदि माननीय सदस्यों की यहां पर सहमति है कि सी0जी0एच0एस0 से करना चाहिये, सरकार करेगी । इसमें कहीं दोमत नहीं है ।

(व्यवधान)

कैशलेस होगा, हंड्रेड परसेंट कैशलेस होगा । जो माननीय सांसद रहे हैं सबको पता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उदय कुमार सिंह जी ।

(व्यवधान)

सरकार स्पष्ट कर दी है, सरकार सहमत है । सरकार आप सबों की राय से सहमत है, डिबेट की आवश्यकता नहीं है । सरकार का जवाब हो गया है, सरकार सहमत है, चिंता मत कीजिये ।

(व्यवधान)

सुझाव के लिये बैठक हो जायेगी । माननीय सदस्य श्री उदय कुमार सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–6, श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–226, शेरघाटी)</u>

श्री उदय कुमार सिंह : महोदय, पूछता हूं ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि डोभी प्रखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजपथ पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी को 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित कर नये भवन का निर्माण कराया गया है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का उपचार किया जाता है। साथ ही लगभग 12 कि0मी0 की दूरी पर संचालित अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी को ट्रामा सेन्टर के रूप में चिन्हित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गंभीर रूप से घायल मरीजों के बेहतर ईलाज हेतु 30 कि0मी0 की दूरी पर स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी रेफर किया जाता है।

टर्न–3 / धिरेन्द्र / 06.02.2026

....क्रमशः....

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, साथ–ही–साथ सात निश्चय–3 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जोंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–179, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या–56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत वैसा प्रखंड में सभी खुले तारों को Revamped Distributor Sector Scheme के अंतर्गत 03 फेज Aerial Bunch Cable से बदल दिया गया है । इसके अलावा सिंगल फेज केबुल से विद्युत आपूर्ति की जा रही है । आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर संचालन एवं संपोषण मद से पुराने तारों को चिन्हित कर बदलने का कार्य किया जाता है।

2– वर्त्तमान वस्तुस्थिति यह है कि उक्त दोनो ग्रामों में विद्युत आपूर्ति 16 Sq-mm Aerial Bunch Cable से की जा रही है, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगाया गया है । उक्त ग्राम में निम्न विभव लाईन का रख–रखाव हेतु संचालन एवं सम्पोषण मद से 03 फेज 50 Sq- mm Aerial Bunch Cable नंदनिया वार्ड नं0–05 के केलालबाड़ी ग्राम में 300 मीटर (लगभग) एवं पलसबाड़ी गाँव में 200 मीटर (लगभग) बदलकर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल की गई है ।

3– उपरोक्त खंडों में स्पष्ट किया गया है ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है लेकिन उससे पहले कि मैं अपने पूरक की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराउं एक बात नीतिगत कहना चाहूँगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । यह सदन बड़ा कीमती है और आवाम के खून एवं पसीने के पैसे से लाखों रुपये एक दिन में खर्च हो रहे हैं और पदाधिकारियों की तरफ से अगर गलत रिपोर्ट आ जाय । विधायक कहता है कि ऐसा नहीं हुआ और पदाधिकारी कहते हैं कि ऐसा होता है । दोनों में कोई एक सच्चा होगा । महोदय, कोई ऐसी समिति बनाइये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय । मैंने कहा है कि मेरे क्षेत्र बैसा में तार जर्जर है और वहां पर सही तौर पर विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है । आर॰डी॰एस॰एस॰ योजना के तहत काम हुआ है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया है लेकिन हमारे क्षेत्र में आर॰डी॰एस॰एस॰ में

क्या हुआ ? कटिहार और पूर्णियां को कंबाइंड टेंडर हुआ और हमारा क्षेत्र आने–जाने में सबसे पिछड़ा है, नदी हैं, नाले हैं, पुल नहीं हैं, कोई ठेकेदार वहां नहीं गया, नतीजा यह हुआ कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के समय भी काम बहुत कम हुआ था और अभी भी हमारे यहां काम नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो रिपोर्ट आपके पदाधिकारी ने दी है, मैं चैलेंज करता हूँ कि वह रिपोर्ट गलत है और वहां पर आज भी हमारा जो मोनी टोला है, पोखरिया है, घटारो है, गेरिया है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, ये जो मनवारे हैं, हफनिया है, ये सब गांव में तार लटक रहे हैं, कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं । महोदय, गोशाला में एक लड़की मर गई।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप लिख कर भेज दीजिये, हम करवा देंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, ठीक है । मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा है कि लिखित पर हो जायेगा । बहुत–बहुत शुक्रिया ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–180, मो॰ सरवर आलम (क्षेत्र संख्या–55, कोचाधामन)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कोचाधामन प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित कर नये भवन का निर्माण कराया गया है । वर्तमान में उक्त अस्पताल में पदस्थापित 3 सामान्य चिकित्सक, एक दन्त चिकित्सक एवं अन्य 12 कर्मियों द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं । विभागीय राज्यादेश सं०–550(10) दिनांक–11.04.2025 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पदसृजन किया गया है । चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है । साथ ही सात निश्चय–3 (2025–2030) अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

मो॰ सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है परन्तु उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें मैंने पूछा था कि वर्ष 2024 में पी॰एच॰सी॰ सेंटर को सी॰एच॰सी॰ सेंटर में अपग्रेड कर दिया गया था लेकिन जो व्यवस्था होती है उसकी कोई भी उपलब्धता नहीं है जिस तरह से सी॰एच॰सी॰ सेंटर में होना चाहिए । सिर्फ नाम बदल दिया गया है लेकिन उसमें कोई भी सुविधा उसके अनुसार जो छः विशेष डॉक्टर होने चाहिए, सर्जन होने चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए और एक बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए, एनेस्थीसिया होना चाहिए । उसके अनुरूप कुछ भी उपलब्ध नहीं है

कोचाधामन के सी॰एच॰सी॰ में और यह कोचाधामन किशनगंज से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को उनकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि सात निश्चय–3 के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है । इस क्रम में पूर्व से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त दो शय्या के आई॰सी॰यू॰, गहन एवं चिकित्सा इकाई, इस तरह से हड्डी रोग, नेत्र रोग, ई॰एन॰टी॰ का, ये सात निश्चिय–3 के तहत होने वाला है । इसलिय माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का यही जवाब है जो मैंने आपको दिया है। वस्तुस्थिति यह है कि कोचाधामन प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित कर नये भवन का निर्माण कराया गया है, आपकी जानकारी के लिए । वर्तमान में उक्त अस्पताल में पदस्थापित 3 सामान्य चिकित्सक, एक दन्त चिकित्सक एवं 12 कर्मियों द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है । विभागीय राज्यादेश सं०–550(10), दिनांक–11.04.2025 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पदसृजन किया गया है । चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है । साथ–ही–साथ सात निश्चय–3 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है तो माननीय सदस्य को और क्या सुविधा चाहिए ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, अब आप बैठ जाइये ।

मो॰ सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2024 में जब अपग्रेड कर दिया गया है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ और आप कब तक करायेंगे ? वहां पर अभी तक आपका एक्स–रे डिजिटल नहीं हुआ है, वहां पर आपका ई॰सी॰जी॰ का प्रावधान नहीं हो रहा है, वहां पर जो पुराना एक्स–रे है उसको डिजिटल करा दिया जाय । उसे कब तक करायेंगे ? आपने कहा है कि इसको अपग्रेड कराया जायेगा सात निश्चय–3 वर्ष 2025–30 में लेकिन जब यह वर्ष 2024 में अपग्रेड हो गया है तो इसको कब तक करा देंगे ? वह बहुत ही इंटीरियर इलाका है, जिससे लोगों की वहां पर आये दिन मौतें हो रही हैं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बता दीजिये ।

मो॰ सरवर आलम : महोदय, उधर अगर कहीं घटना हो जाय, कोई एक्सीडेंट हो जाय तो वहां के लोग किशनगंज तक नहीं पहुँच पाते हैं और सबसे ज्यादा वहां गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर दिक्कतें हो रही हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य, टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है और जो वर्तमान सरकार है इस वर्तमान सरकार में जो नये मेडिकल कॉलेज खुले हैं । आपके समय में छः ही मेडिकल कॉलेज थे इतने बड़े बिहार में । आपके राज में इतने अनुमंडल में इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं थे....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद जी, प्रमोद बाबू ।

मो॰ सरवर आलम : महोदय, मैं कह रहा हूँ कि जब अपग्रेड हो गया है तो सुविधाएं मिलनी चाहिए ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : आज इस सरकार की देन है और सरकार का...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद जी, प्रमोद बाबू ।

मो॰ सरवर आलम : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार जो बोली है, सरकार का जो वादा है, मैं उससे सहमत हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद जी ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : आज जितना बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य खुले हैं, उतना पहले नहीं थे माननीय सदस्य की भावना...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्री प्रमोद जी, आप बैठिये ।

मो॰ सरवर आलम : महोदय, सरकार जो काम कर रही है स्वास्थ्य में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में, महोदय, मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसमें सुधार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इनका सुझाव जो आया है उसको दिखवा लीजिये । दिखवा कर जल्द पूरा करवाइये ।

(व्यवधान)

विषय इतना ही है । आपलोगों को अनुमति नहीं दी गयी है, बिना अनुमति के मत बोलिये । बैठिये । इनकी बातों को प्रोसीडिंग में नहीं ली जायेगी । आप बैठिये ।

(व्यवधान)

उनका सवाल है । आप पहले बैठिये । आपको हमने अनुमति नहीं दी है । उनका दो पूरक हुआ है । माननीय मंत्री, आप बता दीजिये कि कब तक हो जायेगा ।

मो॰ सरवर आलम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि डिजिटल एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करा दी जाय ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, सात निश्चय–3 के तहत सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका सुझाव सही है और सरकार ने संज्ञान में ले लिया है । विश्वास कीजिये कि इसे जल्द ही पूरा करा लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–181, मो॰ फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या–21, ढाका)

मो॰ फैसल रहमान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था ढाका में ब्लड बैंक खोलने का लेकिन जवाब में आया है कि ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में की गयी है । महोदय, वहां हजारों नौजवान ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें मोतिहारी जाना पड़ता है लगभग 30 किलोमीटर दूर । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार वहां पर कलेक्शन यूनिट खोलने का विचार रखती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग । इसका जवाब नहीं है तो हम इसे स्थगित कर देते हैं ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन मरम्मति योग्य है । इसके मरम्मति हेतु निर्माण एजेंसी बी॰एम॰एस॰आई॰डी॰सी॰एल॰ द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के चहारदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न ब्लड बैंक के खोलने के बारे में है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखिये । माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न ब्लड बैंक खोलने के संबंध में है । इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है । यह प्रश्न स्थगित हुआ, अगले तिथि को आयेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–182, श्रीमती मीना कुमार (क्षेत्र संख्या–34, बाबूबरही)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खजौली प्रखण्ड के चतरा गबरौड़ा उत्तर, चतरा गबरौड़ा दक्षिण, ईनरवा, चन्द्रीह, कन्हौली, भकुआ पंचायत में किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु कुल 40 सर्किट कि०मी० 11 के०वी० लाईन, 105 कि0मी0 एल०टी० लाईन एवं 82 अदद् वितरण ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किये जा चुके हैं । इन पंचायतों में इच्छुक कुल 614 किसानों से प्राप्त आवेदन के विरुद्ध 574 किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं । शेष बचे हुए 40 किसानों के

लिए विद्युत संरचना का निर्माण किया जा रहा है एवं कार्य पूर्ण करने मार्च–2026 है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जवाब आपको मिला है तो पूरक पूछ लीजिये ।

टर्न–4 / अंजली / 06.02.2026

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, हमको जवाब मिला हुआ है, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी जो जवाब दिये हैं वह पूरी तरह गलत है क्योंकि हमें दो दिन पहले जवाब मिला था ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती मीना कुमारी : जी महोदय । हमें दो दिन पहले जवाब मिला था, मैं सारा सर्वे कराकर आई हूं, चतरा गबरौड़ा उत्तर में 50 किसान, चतरा गबरौड़ा दक्षिण में 40, ईनरवा में 40, कन्हौली में 35 एवं चन्द्रीह में 25 कुल 190 किसानों का कनेक्शन ले चुका है और अभी तक पोलिंग और वायरिंग नहीं हुआ है लेकिन जवाब जो मिला है कि मात्र 40 किसान का ही पेंडिंग है तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वे एक उच्च स्तरीय जांच करके उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें जो हमेशा गलत जवाब देकर भेजते हैं और मैं आग्रह करूंगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप लिखकर दे दीजिए हम दिखवा लेंगे ।

श्रीमती मीना कुमारी । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्रीमती मनोरमा देवी

तारांकित प्रश्न सं॰–183, श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र सं॰–232, बेलागंज)

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन मरम्मती योग्य है । इसकी मरम्मती हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के चहारदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलागंज के चहारदीवारी निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–198 (10), दिनांक–04.02.2026 द्वारा निर्माण एजेन्सी (BMSICL) से प्राक्कलन की मांग की गयी है ।

प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त राशि की उपलब्धता के आधार पर मरम्मती एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य विहित प्रक्रियानुसार स्वीकृति दी जायेगी।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है वह सकारात्मक है और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद

देना चाहती हूं और साथ ही, आग्रह भी करना चाहती हूं कि काम को शीघ्र करवाया जाय ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन मरम्मती योग्य है । इसकी मरम्मती हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के चहारदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलागंज के चहारदीवारी निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–198 (10), दिनांक–04.02.2026 द्वारा निर्माण एजेन्सी (BMSICL) से प्राक्कलन की मांग की गयी है ।

प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त राशि की उपलब्धता के आधार पर मरम्मती एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य विहित प्रक्रियानुसार स्वीकृति दी जायेगी।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–184, श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं॰–231, टिकारी)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि टिकारी प्रखंड के ग्राम पंचायत–छठवां में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, छठवां स्वीकृत एवं संचालित है । उक्त पंचायत के ग्राम– ईगुना, तेतरिया एवं खैरा में भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत एवं संचालित है ।

साथ ही, प्रश्नगत पंचायत के उपर्युक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से लगभग 05–08 किलोमीटर की दूरी पर अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी भी संचालित है।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, छठवां के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये समाहर्ता, गयाजी से विभागीय पत्रांक–197(10), दिनांक–04.02.2026 द्वारा अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रियानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री अजय कुमार : जी महोदय । माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार मुझे सदन में अपनी बातों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है इसीलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । साथ ही साथ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं...

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री अजय कुमार : और टिकारी विधान सभा के महान मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज बनने का मुझे मौका मिला है इस विधान सभा में । मुझे जवाब मिला है, वह संतोषजनक जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अजय बाबू, पूरक पूछ लीजिए ।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखिए ।

श्री अजय कुमार : दिशा की बैठक में मैंने आवाज उठाया है कि गयाजी जिला में 24 ब्लॉक में नल है लेकिन जल नहीं, केवल कागज पर ही मौका मिलता है जिलाधिकारी साहब ने कहा कि टीम गठित कर दिये हैं ।

अध्यक्ष : स्वास्थ्य पर आ जाइए । प्लीज । अजय बाबू ।

श्री अजय कुमार : कहते हैं कि विपक्ष वाला हल्ला करते हैं तो दोनों कमेटी को हमने कहा कि टीम बना दीजिए पक्ष और विपक्ष का ।

अध्यक्ष : अजय बाबू, हेल्थ के बारे में बोलिए । बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

श्री अजय कुमार : संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, हम चाहते हैं कि कब तक करवाइएगा, समय बता दीजिए ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । सुन लीजिए ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि टिकारी प्रखंड के ग्राम पंचायत–छठवां में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, छठवां स्वीकृत एवं संचालित है । उक्त पंचायत के ग्राम–ईगुना, तेतरिया एवं खैरा में भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत एवं संचालित है । साथ ही, प्रश्नगत पंचायत के उपर्युक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से लगभग 05–08 किलोमीटर की दूरी पर अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी भी संचालित है । स्वास्थ्य उपकेन्द्र, छठवां के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये समाहर्त्ता, गयाजी से विभागीय पत्रांक–197 (10), दिनांक– 04.02.2026 द्वारा अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रियानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

श्री अजय कुमार : छठवां ग्राम में कौन सी 6000 की आबादी है, वहां से 10 किलोमीटर टिकारी जाना पड़ता है । दो हॉस्पिटल बना है वहां से पहुंच 2 किलोमीटर है और...

अध्यक्ष : हो गया । माननीय मंत्री जी ने कहा है, वे सहमत हैं । अजय बाबू, माननीय मंत्री जी ने जिला समाहर्त्ता को जमीन के लिए पत्र लिखा है नंबर–1 और सरकार तैयार है ।

श्री अजय कुमार : जी महोदय, डी0एम0 साहब के यहां गया हुआ है । समय बता दीजिए कि कब वहां बनेगा ? जमीन के लिए डी0एम0 साहब के यहां गया हुआ है, जमीन उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो बताया ही । माननीय मंत्री जी एक बार और बता दीजिए, कब तक पूरा हो जाएगा ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : इसमें कहा गया है कि जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, राशि की उपलब्धता के आधार पर, जैसे ही राशि उपलब्ध होगी बना दी जाएगी ।

श्री अजय कुमार : कब तक राशि उपलब्ध हो जाएगी ?

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : इसी वित्तीय बजट में ।

तारांकित प्रश्न सं०–185, श्रीमती अनीता (क्षेत्र सं०–239, वारिसलीगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्रीमती अनीता । उत्तर मिला है आपको ?

श्रीमती अनीता : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए । आप पूछिये, पूछती हूं ।

श्रीमती अनीता : जी महोदय, मैं पूछती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : विधि विभाग को हस्तांतरण हो गया है ।

अध्यक्ष : जी । अगली बार आएगा । बैठ जाइए ।

तारांकित प्रश्न सं०–186, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र सं०–17, पिपरा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, पूछता हूं । जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक–186, दिनांक–02.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत चकिया मन झील में सालों भर पानी रहता है ।

उक्त के आलोक में भूमि के संबंध में वर्णित स्थल को विकसित करने हेतु विभागीय पत्रांक–380, दिनांक–05.02.2026 द्वारा पुनः प्रतिवेदन की मांग विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) से की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मंत्री जी एक समय–सीमा निर्धारित कर दीजिए कि कब तक मंगा कर उसको करवाना चाहेंगे ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, शीघ्र किया जाएगा ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : शीघ्र नहीं, टाइम बताइए न ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, अतिशीघ्र मंगवाई जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रितुराज कुमार

तारांकित प्रश्न सं०–187, श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र सं०–217, घोसी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत काको प्रखंड में 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, काको एवं लोदीपुर लांजो अवस्थित है । उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का 33 के0वी0 फीडर 132/33 के0वी0 ग्रिड शक्ति उपकेन्द्र, जहानाबाद से निकली है जिसकी दूरी लगभग 14.00 KM है । काको प्रखंड के समीपवर्ती नांलदा जिला के एकंगरसराय एवं पटना जिला के मसौढ़ी में 132/33 के0वी0 ग्रिड शक्ति उपकेन्द्र कार्यरत है, जिससे

संबंधित 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है । 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, घोषी की विद्युत आपूर्ति 132/33 के0वी0 ग्रिड शक्ति उपकेन्द्र, बंधुगंज से की जा रही है । वर्तमान समय मे उक्त सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु काको प्रखंड में ग्रिड शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

श्री रितुराज कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और जो भी सब–स्टेशन का जिक्र किया गया है, जो व्यवस्था पहले थी उससे वह सुधरी है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूं । मगर आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर वहां पर काको में जैसे सब–स्टेशन के लिए विचाराधीन है, उसकी जगह अगर ग्रिड बन जाता तो जहानाबाद शहर के उत्तरी इलाके में, शहर में, काको में गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से समस्या होती है, अगर वहां पर ग्रिड बन जाता है तो ग्रिड की क्षमता सब–स्टेशन से ज्यादा होती है, तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर ग्रिड...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । खड़ा होकर बोल दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सुझाव स्वीकार्य है ।

श्री रितुराज कुमार : जी धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–188, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र सं॰–240, सिकन्दरा, अ॰जा॰)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–189, सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र सं॰–81, अलीनगर)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के तारडीह प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्सो नदियामी में 1 आयुष चिकित्सक 2 ए॰एन॰एम॰ वर्तमान में पदस्थापित हैं । जिनके द्वारा मरीजों का समुचित ढंग से इलाज किया जाता है । उक्त संस्थान का भवन जर्जर नहीं है बल्कि मरम्मत की आवश्यकता है ।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कुल 624 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 575 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति–सह–पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है । साथ ही, स्टाफ नर्स ग्रेड–ए के 11389 पदों एवं ड्रेसर के 3326 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचना के

आलोक में लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है । अनुशंसा प्राप्त होते ही पदस्थापन की कार्रवाई जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है आपको ?

सुश्री मैथिली ठाकुर : जी महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : महोदय, जो उत्तर मिला है उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि उसमें लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है बस उसकी मरम्मती की आवश्यकता है लेकिन मैं चाहती हूं एक बार मंत्री महोदय पुनः अवलोकन कराएं क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूं भवन जर्जर स्थिति में है, वहां पर एक छोटे–से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक नहीं हैं, पूर्व में वहां पर दो–दो एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक थे लेकिन अभी नहीं हैं, उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक हैं जिससे मैं सहमत हूं लेकिन हमें वहां पर दो एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर की आवश्यकता है । मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूं, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूं, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूं, तो मैं चाहती हूं कि वे जनहित में इसका निदान करें क्योंकि अति आवश्यक है । पांच से सात पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ–साफ मानना है कि 40 से 50 हजार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं और मेरे पूरे विधान सभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जो दो अलग प्रखंड हैं– घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूं ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : दिखवा लेता हूं अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–190, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र सं॰–211, डिहरी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–326, दिनांक– 02.02.2026 द्वारा वर्णित स्थल को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु जिला पदाधिकारी, रोहतास से विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी. ..

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी और इस सभा में उपस्थित समस्त मंत्रीगण और समस्त...

अध्यक्ष : सीधे पूरक पूछिये आप । उत्तर मिला है आपको ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : समस्त हमारे माननीय सदस्य को मैं डिहरी विधान.. .

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न आपको ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : दो मिनट महोदय ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है आपको ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : महोदय, उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

अध्यक्ष : यह क्वेश्चन ऑवर है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : महोदय, थोड़ा–सा एक मिनट दे दिया जाय । पहली बार आपने हमें मौका दिया है ।

अध्यक्ष : पार्क के बारे में आपने कहा है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : सभी सदस्यों को मेरी तरफ से और डिहरी विधान सभा और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं ।

(क्रमशः)

टर्न–5 / पुलकित / 06.02.2026

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, मैं सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में, डेहरी डालमियानगर अवस्थित है । जो डालमियानगर एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था और वहां एक बाबा झारखंडी मंदिर अवस्थित है जो पुरातत्व काल के वहां पौराणिक धर्म स्थल है।

अध्यक्ष : आप चाहते हैं वहां पार्क बनवाना न ? यह प्रश्न है ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : जी महोदय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए, माननीय मंत्री ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : महोदय, वह पौराणिक स्थल है । वहां अनेकों छठ घाट है, वहां अनेकों हजारों शादियां होती हैं और वहां अभी जाएंगे निरंतर हजारों–हजारों की संख्या में भीड़ होती है, अभी कोई भी पर्व त्यौहार आता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं । माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हो गये हैं ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : वहां अनेक घाट सोन तट पर अवस्थित है जैसे हमारे काशी विश्वनाथ में देखते हैं गंगा आरती होती है, उसी तरह हमारे यहां बाबा झारखंडी महादेव के प्रांगण में सोन आरती भी होती है और हजारों की संख्या में प्रतिदिन भीड़ होती है लेकिन अभी माननीय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइए । जवाब सुनिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 326, दिनांक 02.02.2026 द्वारा वर्णित स्थल को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु जिला पदाधिकारी, रोहतास से विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार सिंह यादव ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : प्रतिवेदन आने दीजिए, कार्रवाई होगी । धैर्य रखिए । इतना स्पष्ट कहा है माननीय मंत्री ने ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : इस विषय पर कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही है? और जिलाधिकारी...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है, उसके बाद सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–191, श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र सं0–203, रामगढ़)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : 1– वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, रामगढ़ के लिए अल्ट्रासाउण्ड मशीन विथ कलर डॉपलर की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन करने हेतु आपूर्त्ति आदेश निर्गत किया जा रहा है।

सामान्यतः सी0टी0 स्कैन मशीन का अधिष्ठापन जिला अस्पतालों में एवं एम0आर0आई0 मशीन का अधिष्ठापन मेडिकल कॉलेज में किया जाता है।

2– वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, रामगढ़ में 04 मूर्च्छक, 03 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा 01 जेनरल सर्जन पदस्थापित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुर्गावती में 03 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं 01 दन्त चिकित्सक पदस्थापित हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नुआंव में 02 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 01 शिशु रोग विशेषज्ञ एवं 01 दन्त चिकित्सक पदस्थापित हैं। रेफरल अस्पताल, रामगढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है, जिनके द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा मुहैया करायी जा रही है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 624 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी तथा 575 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति–सह–पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब टैब पर आया है लेकिन मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत भी है और भ्रामक भी है। हमारा सवाल था कि रामगढ़ विधानसभा के रेफरल अस्पताल, रामगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दुर्गावती और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन और सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 के लिए सवाल था। इसमें जवाब दिया गया है कि अधिष्ठापन के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा रहा है। महोदय, हम जानना चाहते हैं कि कब तक वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात डॉक्टरों की जानकारी के उपलब्ध में जो जानकारी दी गई है, वह जानकारी और चिकित्सा पदाधिकारी दुर्गावती और रामगढ़ रेफरल अस्पताल के द्वारा दी गई जानकारी में बहुत अंतर है । रामगढ़ रेफरल अस्पताल में 13 पद स्वीकृत हैं, जबकि वहां पर मात्र तीन डॉक्टर कार्यरत हैं । दो जनरल फिजिशियन हैं और एक जो है महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ है अभी कुछ दिन पहले।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जवाब सुन लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : यहां पर सात डॉक्टरों को दिया गया है । दुर्गावती में भी वही हाल है, 13 पद स्वीकृत हैं, मात्र दो डॉक्टर कार्यरत हैं । अभी चिकित्सा पदाधिकारी जो दुर्गावती के हैं उन्होंने एक घंटा पहले हमको जानकारी दी, बकायदा लेटर के साथ । इस लेटर में 6 डॉक्टरों का जिक्र किया गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये । अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, झूठी रिपोर्ट भी है और जानकारी गलत भी है ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, इस संबंध में विभाग में दिखवा लेते हैं और जो संभव होगा, उसमें हमलोग सरकार की ओर से कार्रवाई करेंगे ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, गलत रिपोर्ट आई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह भी देख लेंगे । गलत रिपोर्ट भी दिखवा लीजिए ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य को बोला है कि जो संभव होगा, सरकार की ओर से करेंगे । आपने जो प्रश्न किया है वह भी ठीक है और जो सरकार ने जवाब दिया है वह भी ठीक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दिया जाए । क्या उन पर कार्रवाई कीजिएगा और जो डॉक्टरों की जो नियुक्ति करनी है....

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : सर, कब तक कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि शीघ्र करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–192, श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र सं0–38, झंझारपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित किये जाने की योजना के क्रम में लखनौर प्रखंड में 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराते हुए संचालित किया जा रहा है। साथ ही उक्त परिसर में 20 शैय्या का प्रीफैव अस्पताल निर्मित हैं।

उक्त संस्थान में पदस्थापित 02 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 01 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), 01 दन्त चिकित्सक (संविदा) एवं 01 ए०एन०एम० वर्तमान में पदस्थापित हैं जिनके द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया जा रहा है।

विभागीय राज्यादेश संख्या–550(10), दिनांक–11.04.2025 द्वारा मानक के अनुरूप पदसृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

साथ ही सात निश्चय–3 (2025–2030) अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न में है कि जो लखनौर प्रखंड में सी0एच0सी0 निर्मित है, उसी कैंपस में 20 शैय्या का प्रीफैव के एक भवन का निर्माण और किया गया है । माननीय मंत्री महोदय ने ही अपने उत्तर में सी0एच0सी0 का भी जिक्र कर दिया है इसलिए मैं उस सी0एच0सी0 पर भी माननीय मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक सी0एच0सी0 का मानक क्या है अध्यक्ष महोदय? उसमें कितने चिकित्सक होने चाहिए ? कितने ग्रेड ए की नर्स होनी चाहिए ? क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए ? यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वह सब पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मेरा मूल प्रश्न इतना है कि सी0एच0सी0 हम सब जानते हैं कि एक प्रखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है और पी0एच0सी0 को ही प्रखंड में अपग्रेड करके जब पुराना रेफरल अस्पताल का कॉन्सेप्ट था, उसको सी0एच0सी0 के तौर पर अब उसका निर्माण कराया जाता है। 30 बेड वहां पर आज भी ढंग से संचालित नहीं है, अतिरिक्त 20 बेड का निर्माण कराकर 4 सितंबर 2024 को उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के उत्तर में दिया हुआ है कि दो चिकित्सक वहां पर उपलब्ध हैं, दो में एक मधुबनी में प्रतिनियुक्त हैं यानी एक ही हैं । एक वहां पर संविदा के डॉक्टर हैं और एक दंत चिकित्सक हैं। अध्यक्ष महोदय, जो सी0एच0सी0,

लखनौर के प्रभारी हैं, वही झंझारपुर पी0एच0सी0 के भी प्रभारी हैं। उस परिस्थिति में जो लखनौर का हमारा सी0एच0सी0 है, जैसे उदाहरण स्वरूप 16 ए ग्रेड नर्स का वहां पर पद स्वीकृत है, एक भी कार्यरत नहीं है । महोदय, पूरा प्रखंड लगभग 15 ग्राम पंचायतों का है और पूरे 15 ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रमुख सी0एच0सी0 है जो लगभग 5 करोड़ की राशि से भी अधिक से निर्मित है। आज भी देखते हैं तो वह पीड़ा होती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन उस अनुरूप मानव संसाधन पर हमारा ध्यान नहीं गया है । अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है कि जब हम 30 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए हैं, तो ये जो 20 एडिशनल बेड बनाने का औचित्य क्या था ? आज भी डेढ़ वर्षों के बाद वहां ताला लगा हुआ है, जंगल से वह घिर चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करूंगा कि जितने भी सी0एच0सी0 हैं, विशेष तौर से जो मेरा प्रश्न है लखनौर प्रखंड का, उसमें सी0एच0सी0 के मानक के अनुरूप मानव संसाधन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जांच की व्यवस्था साथ ही साथ जो 20 शैय्या का प्रीफैव टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो भवन निर्मित किया है, उसको सिर्फ ये फंक्शनल कर दें, शीघ्र से शीघ्र।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय राज्यादेश संख्या–550(10), दिनांक–11.04.2025 द्वारा मानक के अनुरूप पदसृजन किया गया है । चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

साथ ही सात निश्चय–3 (2025–2030) अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिया है इसलिए मैं पूछ रहा हूं वरना मैं कोई पूरक पूछने वाला नहीं था इनसे । ये स्वीकृति आदेश, सी0एच0सी0 इनका कब फंक्शनल हुआ ? अब ये जो पद सृजन इन्होंने 2025 के अप्रैल महीना का ये बता रहे हैं, सी0एच0सी0 हमारा जब बना, ये जो पद सृजन की इन्होंने स्वीकृति कराई तो वह सी0एच0सी0 जो पूर्व से निर्मित है उसमें क्या करेंगे ? ये जो पद सृजन है ये प्रीफैव के लिए इन्होंने किया है या सी0एच0सी0 के लिए किया है ? जो सी0एच0सी0 आज से पांच वर्ष पूर्व से निर्मित है, पद सृजन इन्होंने नहीं किया तो वह भवन बनाने की इनको आवश्यकता नहीं थी । इसलिए स्वास्थ्य विभाग को यह आवश्यक है कि वह देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ–साथ पैरेलली जो मानव संसाधन है उसको भी वहां पर प्रतिनियुक्त करने का साथ में इनको कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, सिंह : अध्यक्ष महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद ही सारी व्यवस्थाएं खड़ी होंगी, नहीं तो हम सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं । इसलिए ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । कोई डिबेट नहीं, शांति बनाये रखें ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा विधान सभा क्षेत्र है । मैं पांचवी बार का विधायक हूँ झंझारपुर से । वर्ष 2022 से सी0एच0सी0 भवन वहां पर फंक्शनल है । आज लगभग चार वर्ष होने को जा रहे हैं । माननीय मंत्री जी कितना समय और लेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बता दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय स्पष्ट है, माननीय सदस्य माननीय मंत्री भी रहे हैं और उस दौर में, तो वे खुद मंत्री थे । लेकिन जहां तक इस पूरी व्यवस्था का मामला है, 2025 में ही पद का सृजन हुआ है, उसको जल्द से जल्द भरा जाएगा इसमें कहां दो मत है ?

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शिद आलम ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–193, श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र सं0–50, जोकीहाट)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलासी को 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित कर नये भवन का निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है।

विभागीय राज्यादेश सं०–550(10), दिनांक–11.04.2025 द्वारा मानक के अनुरूप पदसृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

साथ ही सात निश्चय–3 (2025–2030) अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है । जवाब में आज भी इसका भेग है । माननीय मंत्री जी लिखे हैं कि वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलासी को 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है।

(क्रमशः)

टर्न–6 / हेमन्त / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : और बिहार सरकार की जो विभागीय चिट्ठी है कि 11.04.2025 के द्वारा जो उसमें सीएचसी का मानक है, उसको भी फंक्शनल करा दिया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि हमारी प्रभारी चिकित्सा प्रभारी से बात हुई है वह 6 बेडेड से पहले से था। आज अगर वह 30 बेडेड का किया जा रहा है, तो क्या वह फंक्शनल है। आप डेट दे दिये, आप सब चीज दे दिये कि नयी बिल्डिंग बनाकर आपने कराया है, लेकिन वह फंक्शनल ही नहीं है। आज भी वहां पर 30 बेड लगा हुआ नहीं है। यह सभी जानकारियां गलत हैं। आप वहां प्रभारी से पूछ लीजिए, सिविल सर्जन से पूछ लीजिए। जहां से हम लोग हैं, वहां देखकर आते हैं, पूछकर आते हैं, कहिये तो हम फोटोग्राफी करा देते हैं, आज भी 6 बेड लगा हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : विभागीय जांच हम इसकी करायेंगे और आप भी उसमें रहेंगे।

अध्यक्ष : सरकार सहमत है। सरकार जांच करायेगी, कार्रवाई करेगी और आप भी रहेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या–194, श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र सं0–91, बोचहां (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मैदापुर के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा निविदा निष्पादित करते हुए संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया गया था, जिनके द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के निर्धारित तिथि तक मात्र छत तक के कॉलम कास्टिंग का कार्य ही किया गया। निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संवेदक को कालीकृत कर दिया गया है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है, लेकिन मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। तीन साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि समय–सीमा तय करें कि कब तक यह भवन बनेगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मैदापुर के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा निविदा निष्पादित करते हुए संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया गया था, जिनके द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के निर्धारित तिथि तक मात्र छत तक के कॉलम कास्टिंग का कार्य ही किया गया। निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण

संवेदक को कालीकृत कर दिया गया है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : स्पष्ट हो गया है। सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे निर्माण भी होगा।

श्रीमती बेबी कुमारी : सर, कब तक होगा ?

अध्यक्ष : अब टेंडर होगा। टेंडर के बाद ही न होगा। हो जायेगा।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसकी बहुत आवश्यकता है।

अध्यक्ष : धन्यवाद दे दीजिए। कार्रवाई हो रही है और आगे बनने जा रहा है।

श्रीमती बेबी कुमारी : मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–195, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक है।

विभागीय पत्रांक–220(7), दिनांक 20.09.2023 के द्वारा सहरसा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.05.2025 के मद संख्या–12 में दी गयी स्वीकृति के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0–487(6), दिनांक 19.05.2025 द्वारा सहरसा जिलान्तर्गत अंचल–सत्तरकटैया के मौजा–सत्तर, थाना संख्या–173 के खाता संख्या–754 के विभिन्न खेसरा में कुल प्रस्तावित रकबा–21.27 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

सात निश्चय–3 के अन्तर्गत नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) को प्रोत्साहित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आलोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह प्रश्न जो मैंने पूछा था कि सहरसा में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने से संबंधित जवाब तो मिला है। अब पूरक पूछेंगे तो पता नहीं कि मंत्री जी क्या जवाब देंगे, लेकिन मेरा जो कन्सर्न है वह यह है कि 2023 में इनप्रिंसिपल एप्रूवल मिला था मेडिकल कॉलेज खोलने का और जमीन का जो हस्तांतरण हुआ है, एक्विजीशन हुआ है वह 2025 में हुआ है और इसमें दो साल लगे हैं। इसी से संबंधित मेरे दो–तीन प्रश्न हैं। एक यह है कि सहरसा में सदर हॉस्पिटल जो है उसके पास 21 एकड़ जमीन है और एजुकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहला पूरक यह है कि क्या सरकार तात्कालिक रूप

से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस सदर हॉस्पिटल में खोलने का विचार रखती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, जवाब समझ गये उनका। मैं समझ गया। वह फिर वही पढ़ देंगे। दूसरा यह है कि सरकार कह रही है कि Public Private Partnership में हम इसको ओपन करेंगे, तो यह कब टेंडरिंग प्रोसेस में जायेगा और यह जो Public Private Partnership मेथडोलॉजी होगा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरा संपत्ति लगाकर एयरपोर्ट बना दें और किसी को दे दें। उस मॉडल पर तो नहीं होगा ? तो हमारा यह कन्सर्न है कि अगर पब्लिक पार्टनरशिप में यह जायेगा, तो क्या इसका बोझ सहरसा के लोगों को वहन करना पड़ेगा ? इस चीज को भी देखना पड़ेगा। पहला कि क्या मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को, जो वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसमें हो सकता है कि नहीं। दूसरा, कि टेंडरिंग प्रोसेस में कब जायेंगे और Public Private Partnership मोड की मेथडोलॉजी क्या होगी, यह हम जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता है, सरकार की भी चिंता है। बगल में मधेपुरा मेडिकल कॉलेज सरकार ने स्थापित किया, लेकिन आज की परिस्थिति में डॉक्टर्स को जब भी पदस्थापित किया जाता है, नहीं जाते हैं। इसके लिए आगे पॉलिसी भी बना रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी करेंगे उनको हम किसी भी हालत में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। इसके लिए पॉलिसी बन रही है। लेकिन जो चिंता है माननीय सदस्य की कि उसी जगह पर जहां सदर अस्पताल है, उस जगह की हम लोगों ने पूरी तरह समीक्षा करायी थी, मैं स्वयं भी उस जगह पर गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये थे, जिस जमीन पर बनना है, दोनों चीजों को देखा है। लेकिन इसके बावजूद यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो जरूर उसकी समीक्षा कराता हूं कि उस पर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। इसकी एक रिपोर्ट मांगता हूं। दूसरा, जो पी0पी0पी0 मोड है इसकी एक पॉलिसी हम बना रहे हैं। सरकार इसको तय करेगी। स्वाभाविक है, जैसा मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा में सारी व्यवस्था देने के बावजूद, सारी चीजों को देने के बावजूद वहां डॉक्टर नहीं रहते हैं, बेतिया नहीं रहते हैं। तो वहीं से यह सोच भी आयी है कि हमको पी0पी0पी0 मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए पी0पी0पी0 मोड पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पॉलिसी जब आयेगी तो माननीय सदस्य को विस्तार से बताया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–196, श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या–163, बेलहर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–197, श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या–66, प्राणपुर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राणपुर में 03 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 01 दन्त चिकित्सक एवं 01 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत है जिनके द्वारा रोगियों का समुचित इलाज किया जा रहा है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) के 258 पदों की अनुशंसा प्राप्त हो गयी है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति–सह–पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब संतोषजनक है। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

तारांकित प्रश्न संख्या–198, श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या–187, मनेर)

श्री भाई वीरेन्द्र : पूछता हूं। उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो अपलोड किया गया है, लेकिन माननीय सदस्य को नहीं पहुंचा है, तो हम फिर से पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष : ये पढ़ नहीं पाये हैं। ये पढ़े ही नहीं हैं।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, पटना का पत्रांक–237, दिनांक–03.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना जिला अन्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत हल्दी छपरा कित्ता चौहत्तर पश्चिमी के निकट अवस्थित है। उक्त स्थल के समीप 03 नदियों का मिलन है, यथा–गंगा, सोन एवं सरयुग नदी। विभिन्न त्यौहारों जैसे छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा में संगम स्थल पर ग्रामीण जनता एवं सुदूर क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपस्थित होकर यहां पर स्नान ध्यान एवं पूजा–पाठ किया जाता है। संगम हल्दी छपरा घाट से करीब 200 मीटर नदी के बीच में है। जहां स्थानीय नाव के माध्यम से निवासी आवागमन करते हैं। घाट से लगी हुई जमीन गंगा की प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है एवं कोई बसावट नहीं है।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

विभागीय पत्रांक 375, दिनांक 04.02.2026 द्वारा उक्त स्थल को विकसित करने हेतु भूमि से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी, पटना से की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : इतना स्पष्ट जवाब दिया इन्होंने।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि वहां ग्रामीण नहीं हैं। वहां गांव बसा हुआ है, हम वहां के एम0एल0ए0 हैं, वहां गांव बसा हुआ है और सरकार का जो पदाधिकारी रिपोर्ट दे रहा है, गलत दे रहा है। माननीय सांसद भी बैठे हुए हैं, मंत्री हैं यहां, ये भी जानते हैं कि वहां...

अध्यक्ष : सांसद थे।

श्री भाई वीरेन्द्र : वही कह रहे हैं कि सांसद थे और अभी मंत्री हैं, यह मैंने कहा। यह भी जानते हैं वहां की स्थिति कि वहां निश्चित रूप से गंगा, सरयू और सोन नदी बहती है, वहां पर्यटक स्थल घोषित करने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

अध्यक्ष : सरकार चाह रही है।

श्री भाई वीरेन्द्र : और कई बार इस तरह का क्वेश्चन हुआ।

अध्यक्ष : इसीलिए डी0एम0 से प्रतिवेदन मांगा गया है। प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जायेगी।

श्री भाई वीरेन्द्र : वहां एकदम नजदीक में गांव है।

अध्यक्ष : श्री माधव आनंद।

श्री भाई वीरेन्द्र : सर, एक बार और....

अध्यक्ष : अभी और क्वेश्चन हैं। इतना साफ जवाब आया है कि प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जायेगी। माननीय मंत्री जी, एक लिखित भेज दीजियेगा।

श्री माधव आनंद।

तारांकित प्रश्न संख्या–199, श्रीमती स्नेहलता (क्षेत्र संख्या–208, सासाराम)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी को प्राधिकृत किया गया है।

(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 27, दिनांक 02.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिला स्थित रोहतासगढ़ किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना प्रमंडल के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है जिसे वर्ष 1915 में गजट नोटिफिकेशन BO1814-E दिनांक 01.12.1915 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस स्मारक के संरक्षण एवं रख–रखाव संबंधी कार्य आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निष्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में भी स्मारक के संरक्षण एवं विकास कार्य प्रस्तावित है। वन प्रमाण्डल पदाधिकारी, रोहतास, वन प्रमण्डल, सासाराम का पत्रांक 413, दिनांक 31.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास वन प्रमण्डल के चेनारी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत अवस्थित शेरगढ़ किला कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। पर्यटकों के शेरगढ़ किला पर आवागमन हेतु वन विभाग द्वारा सीढ़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया है। साथ ही, पर्यटकों की सुविधाओं हेतु शेरगढ़ किला की साफ–सफाई कार्य समय–समय पर किया जाता है।

पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में रोहतासगढ़ किला पर नए आकाशीय रज्जूपथ (Ropeway) का अधिष्ठापन हेतु 1265.15 (बारह करोड़ पैंसठ लाख) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त योजना का कार्य प्रगति पर है।

वर्तमान में रोहतास जिले के सासाराम में शेरगढ़ किला तक पहुंचने के लिए रोपवे निर्माण के संबंध में कोई योजना नहीं है।

श्री माधव आनंद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष : पूछिये।

श्री माधव आनंद : मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि रोहतासगढ़ किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना प्रमंडल के अंतर्गत संरक्षित है और इसके संरक्षण में विकास का काम प्रस्तावित है।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री माधव आनंद : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रस्तावित विकास का विवरण क्या है ? दूसरा, उत्तर में कहा गया कि किला का कुछ भाग....

अध्यक्ष : माधव जी, आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री माधव आनंद : पूरक ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष : आपका रोपवे के निर्माण के संबंध में है।

श्री माधव आनंद : जी हां।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

टर्न–7 / संगीता / 06.02.2026

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–27 दिनांक–02.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिला स्थित रोहतासगढ़ किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना प्रमण्डल के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है जिसे वर्ष 1915 में गजट नोटिफिकेशन BO1814-E दिनांक– 01.12.1915 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है । इस स्मारक के संरक्षण एवं रख–रखाव संबंधी कार्य आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं । वर्तमान में भी स्मारक के संरक्षण एवं विकास कार्य प्रस्तावित हैं । वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम का पत्रांक–413 दिनांक–31.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास वन प्रमंडल के चेनारी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत अवस्थित शेरगढ़ किला कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है । पर्यटकों के शेरगढ़ किला पर आवागमन हेतु वन्य विभाग द्वारा सीढ़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया है । साथ ही, पर्यटकों की सुविधा हेतु शेरगढ़ किला की

साफ–सफाई कार्य समय–समय पर किया जाता है । पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में रोहतासगढ़ किला पर नए आकाशीय रज्जूपथ (Ropeway) का अधिष्ठापन हेतु 1265.15 (बारह करोड़ पैंसठ लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । उक्त योजना का कार्य प्रगति पर है । वर्तमान में रोहतास जिले के सासाराम में शेरगढ़ किला तक पहुंचने के लिए रोपवे निर्माण के संबंध में कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायें । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–6 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हैः– श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री राहुल कुमार, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0, श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री रणविजय साहू, स0वि0स0 ।

आज दिनांक–06 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–171(1) एवं नियम–47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर कार्य–स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, इसलिए हम समझते हैं कि इस पर कार्य स्थगित करके इस पर विमर्श करना चाहिए सदन को...

अध्यक्ष : ठीक है, आप पढ़ लीजिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, रबी सीजन में किसानों को यूरिया की भारी कमी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । सरकारी दरें क्रमशः 266 रुपये निर्धारित है, किन्तु बाजार में यूरिया 370 से 450 रुपये प्रति बैग तक बिक रहा है । सरकार के गलत आकलन और आपूर्ति प्रबंधन की विफलता के कारण किसानों को ऊंचे दामों पर बाजार से खाद खरीदने के लिए विवश है । कार्रवाई के नाम पर केवल खुदरा विक्रेताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि बड़े थोक व्यापारी बच निकलते हैं । साथ ही, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के भ्रष्टाचार के कारण किसानों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः दिनांक–06.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार के किसानों को राहत देने हेतु खाद की पर्याप्त आपूर्ति, मूल्य नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री नन्द किशोर राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर में रामनगर बाजार एवं हरिनगर शुगर मिल है, इनके बावजूद भारी वाहनों का आना–जाना है, इसलिए रामनगर–लौरिया, रामनगर–नरकटियागंज, रामनगर–गोबर्धना मार्गों के लिए रामनगर से बाहर बाईपास हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र हरिनगर गांव में कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा व्यक्तिगत मामला को जातिगत रंग देकर एक ही समुदाय के पूरे गांव के लोगों पर SC/St एक्ट के तहत अभियुक्त बनाया गया जो अत्यंत चिंताजनक है । निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला में बी0पी0एल0 मद का नवम्बर एवं दिसंबर माह 2025 का करीब 5000 मे0 टन खाद्यान्न व्ययगत हो गया है, सरकार दोषियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : श्री रोमित कुमार ।

(व्यवधान)

डिबेट नहीं होगा, सरकार ने संज्ञान ले लिया है । सरकार कार्रवाई करेगी । श्री रोमित कुमार, आप पढ़िए ।

श्री रोमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया केन्द्रीय कारागार का नामांकन शहीद वैकुण्ठ शुक्ल के नाम पर किया जाये क्योंकि अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष में उन्हें इसी जेल में फांसी दी गयी थी । जैसे मुजफ्फरपुर व भागलपुर जेल का नामाकरण खुदीराम बोस व जुब्बा सहनी के नाम पर हुआ उसी प्रकार गया जेल का नामाकरण हो।

श्रीमती बिनिता मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखण्ड 45 कि0मी0 दूर रजौली अनुमण्डल में है, जिस कारण आम जनता को जनसुविधा, प्रशासनिक सुगमता में काफी कठिनाई होती है, जबकि 15 कि0मी0 नवादा अनुमण्डल है, सरकार से रोह प्रखण्ड को रजौली अनुमण्डल से हटाकर नवादा अनुमण्डल में शामिल करने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता देवी, आपका शब्द ज्यादा था, आपको मौका दिया गया है । आगे से 50 शब्दों में ही दीजिएगा ।

श्रीमती संगीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की रंगा–मटिया से बारसोई मुख्य सड़क पर खुराधार नदी पर पुल निर्माण का मामला जिला योजना समिति (क्रमांक–175) से स्वीकृत है । इस पुल के अभाव में क्षेत्र की 8–10 पंचायतों के ग्रामीणों को अनुमंडल मुख्यालय एवं अस्पताल जाने हेतु 20–25 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है । अतः जनहित में सरकार से उक्त पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने की मांग करती हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधान सभा अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखण्ड के करियन गांव में लगभग 4 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है । स्टेडियम निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ प्रखंड में ममहान गांव के पुल से ग्राम–जिगनी तक नहर मरम्मत एवं पूर्वी पटरी का पक्कीकरण कराने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री मो0 कमरूल होदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला किशनगंज, पूर्णियां, कटिहार, अररिया सहित पूरे राज्य के जनवितरण प्रणाली डीलरों को जुलाई 2025 से अब तक मार्जिन मनी का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है, फलस्वरूप वे आर्थिक रूप से परेशान हैं ।

अतः मैं डीलरों को अविलंब मार्जिन मनी भुगतान की मांग करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवर्षा प्रखण्ड में पानी का जलस्तर बहुत नीचे जाने के कारण चापाकल सूख जाता है और पेयजल के लिए हाहाकार मच जाता है, सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवर्षा प्रखण्ड में गर्मी आने से पहले जल सभी घरों में पहुंचाने की मांग करती हूं ।

टर्न–8 / यानपति / 06.02.2026

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर वि0स0 के नागर उच्च विद्यालय पहाड़पुर के पास 5.5 एकड़ जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम से पंजीकृत है । विद्यालय के पास 18 कमरा, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, सभागार, साईकिल स्टैंड, जिम, जेनरेटर, फुटबॉल स्टेडियम आदि है ।

अतः सरकार से नागर उच्च वि0 को अधिग्रहण करने की मांग करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड हायाघाट के छात्र–छात्राओं को 10+2 करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु कोसों दूर जाना पड़ता है ।

अतएव मैं सरकार से उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर प्रखंड के पोडंगा (लाभा) में एन0एच0–31 पर स्थित आर0सी0सी0 पुल का अलाईनमेंट टेढ़ा होने तथा तीव्र मोड़ होने के कारण एक्सीडेंट से हाल में कई लोगों की मृत्यु हो गई है ।

सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर मैं पुल के पुनर्निर्माण की मांग सरकार से करती हूं ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलांतर्गत फलका प्रखंड में बरेटा मध्य विद्यालय का भवन पांच वर्षों से निर्माणाधीन है, जिसका दो वर्ष से लगभग निर्माण कार्य बंद है ।

अतएव कार्य में लापरवाह संवेदक पर कार्रवाई करने के साथ उक्त निर्माण कार्य कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अंतर्गत शेरघाटी एन0एच0–2 हाईवे से मोरार नदी के किनारे होते हुए चेरकी तक का रोड जो गुरूआ, परैया, बोधगया, गयाजी को जोड़ता है यह रोड शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित है यह पथ पर जाम की हमेशा समस्या बनी रहती है ।

अतः जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु रिंग रोड निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

श्री अविनाश मंगलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत बैजनाथपुर ग्राम जिसकी आबादी 6000 है । फरियानी नदी के पनभरनी घाट पार कर जाने का एक मात्र रास्ता है । सरकार फरियानी नदी के पनभरनी घाट पर पुल का निर्माण करावे ।

श्री रामचंद्र सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलांतर्गत अलौली विधान सभा के कोशी क्षेत्र में पंचायत आनंदपुर मारण के मारनडीह में सी0एच0सी0 की आवश्यकता है । इसलिए उक्त स्थानों पर सी0एच0सी0 का निर्माण कराया जाय ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु 20–30 कि0मी0 दूर जिला मुख्यालय/सीमावर्ती जिला जाना पड़ता है, समय और आर्थिक अभाव में छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।

छात्रहित में मोरवा प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिलांतर्गत प्रखंड बगहा–2 के रामपुर से हरनाटाड़ तक जानेवाली सड़क चौड़ीकरण नहीं रहने के कारण आये दिन भीषण जाम एवं दुर्घटनाएं घटित रहती है, जिससे राहगीरों को काफी कठिनाई होती है, मैं सरकार से चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण की मांग करता हूं ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत अलीनगर विधान सभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शिक्षा प्रणाली के तहत एक समग्र, लचीली, समावेशी तथा मातृभाषा में शिक्षा के तर्ज पर विलुप्त हो रही संस्कृति और मिथिलाक्षर को बचाने हेतु पंचायतों में मिथिलाक्षर केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत चकहबीब, वार्ड संख्या–09 अल्पसंख्यक टोला से मुख्य सड़क तक आवागमन

के लिए कोई संपर्क सड़क नहीं है जिसके कारण लोगों को पगडंडी से आना–जाना पड़ता है ।

मैं सरकार से उक्त अल्पसंख्यक टोला में संपर्क सड़क का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, BPSC के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में TRE-4 का जिक्र नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी निराशा और आक्रोश है ।

अतः कंप्यूटर साइंस के 26,000 पदों को जोड़ते हुए कुल 1 लाख रिक्त पदों पर डोमिसाइल नीति के साथ TRE-4 का विज्ञापन तत्काल जारी करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कार्यस्थल के अनुसार मेरे साथ पूर्णिया जिला बल से प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता का लाभ मुख्यालय (पटना) के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है ।

अतः मैं सरकार से मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता मुख्यालय (पटना) के अनुरूप देने की मांग करता हूं ।

मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड में एक भी खेल स्टेडियम न होने से हजारों ग्रामीण युवा अपनी प्रतिभा खो रहे हैं । युवाओं के शारीरिक विकास और खेल प्रोत्साहन हेतु मैं सरकार से यहां अविलंब आधुनिक स्टेडियम निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के पी0एच0सी0 डगरूआ में 7 स्वीकृत चिकित्सक पदों में केवल 2 पदस्थापित है जिनमें 1 अन्यत्र प्रतिनियुक्त है । वही पी0एच0सी0 बायसी में 6 पदस्थापित चिकित्सकों में 4 अन्यत्र प्रतिनियुक्त व 1 अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है । प्रतिनियुक्ति रद कर मूल स्थान पर पदस्थापन की मांग करता हूं ।

मो0 मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत जोकीहाट प्रखंड के चकई ग्राम पंचायत अंतर्गत करहमना गांव परमाण धार के दोनों किनारे बसा हुआ है, गांव के निकट उक्त धार में पुल नहीं रहने के कारण उक्त गांव का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा हुआ है ।

अतः उक्त पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम में स्ट्रीट लाइट के नाम पर गंभीर घोटाला हुआ है । करोड़ों खर्च के बावजूद कलेक्ट्रेट रोड, डी0एम0 आवास रोड सहित प्रमुख सड़कें अंधेरे में हैं । यह सरकारी धन की लूट है। अतः सरकार बताए उच्चस्तरीय जांच व दोषियों पर कार्रवाई कब होगी ?

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत–08 प्रखंड पड़ता है, जो जिला का सबसे बड़ा अनुमंडल है । उक्त अनुमंडल में उप–कोषागार नहीं रहने के कारण ट्रेजरी कार्य हेतु सासाराम जाना पड़ता

है । अतः मैं बिक्रमगंज अनुमंडल स्थित उप–कोषागार कार्यालय स्थापित करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलांतर्गत चकाई प्रखंड की जनसंख्या लगभग पांच लाख के करीब है । इस कारण चकाई प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा दिलाने हेतु मैं मांग करती हूं ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलांतर्गत काशीचक थाना हाजत में दिनांक–26.11.2025 को सन्नी कुमार, ग्राम–बौरी की मौत हो गयी । उनके परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

अतः मृतक सन्नी कुमार के परिजनों को मुआवजा दिलवाने एवं मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग करती हूं ।

टर्न–9 / मुकुल / 06.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे और ध्यानाकर्षण उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह । इनकी सूचना पढ़ी हुई है। माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य</u>

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा मांझा अंचल अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये कुल 24 एकड़ 37 डिसीमील चिन्हित भूमि की उपयुक्तता की जांच हेतु विभागीय पत्रांक–145(1), दिनांक–02.02.2026 द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के तकनीकी दल से स्थल निरीक्षण कराये जाने के लिए प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को निदेशित किया गया है ।

भूमि उपयुक्तता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंजीत कुमार सिंह ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद् के निर्णय हैं जो दिनांक–05.09.2023 को लिये गये थे । अध्यक्ष महोदय, यह 2023–24 का सरकार का निर्णय है और निर्णय है पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए और लगभग 2 अरब 99 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के बाद बी0एम0आई0सी0एल0 ने दिनांक–20.10.2023 को निविदा भी प्रकाशित किया लेकिन 2023 के मामले अब तक लंबित हैं

और जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने यह प्रतिवेदित किया कि मांझा के धनखर में यह मेडिकल कॉलेज के लिए माननीय मंत्री जी ने 14 एकड़ का जबकि वह 24 एकड़ 37 डिसीमिल है । अध्यक्ष महोद, अब हम जानना चाहते हैं कि जब डी0एम0, गोपालगंज ने यह पत्र लिखा और पत्र लिखे 11 महीने हो गये तो आज तक कोई समिति का गठन करके जांच सरकार अब तक क्यों नहीं कराई है, यह 2023–24 का मामला है और 2025–26 से सत्र शुरू होने थे, यह सरकार के निर्णय थे तो मंत्री जी यह बता दें कि कितने दिनों के अंदर यह अपनी टेक्निकल टीम भेजकर स्थल का, मांझा धनखर का जांच करा के और मेडिकल कॉलेज के लिए पुनः निविदा करके और मेडिकल कॉलेज का निर्माण सुनिश्चित करायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय लोग इसमें जांच करेंगे और इन्होंने जो कहा है कि जिला अधिकारी उन्होंने जमीन दिया है लेकिन वह जमीन....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वहां पर टेक्निकल टीम भेजनी है ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल टीम भेजकर के जमीन उपयुक्त है कि नहीं है, अस्पताल बनने योग्य जमीन है कि नहीं है, वह कितनी दूरी है क्या है जो एक मेडिकल कॉलेज के दृष्टिकोण से वह उपयुक्त है कि नहीं है इसको दिखाने के बाद उस पर हमलोग कार्रवाई करेंगे ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह निर्णय है और 2023–24 का मंत्रिपरिषद् का यह निर्णय है महोदय और 2 अरब 99 करोड़ सरकार ने स्वीकृत की और आज तक यह 2026–27 का बजट हो गया, 11 महीने जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने पत्र लिखा तो विभाग अब तक जांच क्यों नहीं कराई, क्यों विलंब हो रहा है इसके संबंध में हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : ठीक है ।

सर्वश्री अजय कुमार, अरूण सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार जी आपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा लागू एन0ई0पी0 2020 और एन0सी0एफ0–एस0एफ0 2023 के दिशा–निर्देशों के अनुसार, स्कूली शिक्षा में ललितकला, संगीत और खेल को अनिवार्य विषयों की श्रेणी में रखा गया है । इन विषयों का उद्देश्य छात्रों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है । इस संदर्भ में बिहार की वर्तमान स्थिति काफी चिन्ताजनक है । बिहार में कुल 9360 माध्यमिक विद्यालय हैं, जबकि ललितकला का पद मात्र 686 तक ही सीमित है । वर्ष–2015 के बाद पदों का सृजन नहीं किया गया है । वर्तमान नियुक्तियों (TRE-2.0 और TRE-3.0) में पदों की

संख्या अत्यंत कम है । क्रमशः 284 और 40 रही है, जिसके कारण कला शिक्षकों की भारी कमी है । वर्तमान में लगभग 8000 योग्य अभ्यर्थी ललित कला विषय में एस0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण होकर नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं । कला शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के छात्र अपनी रचनात्मक प्रतिभा निखारने से वंचित रह रहे हैं ।

अतः राज्य के सभी 9360 माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात के आधार पर ललितकला विषय के पदों को सृजन करते हुए बी0पी0एस0सी0 टी0आर0ई0 4.0 की अधिसूचना में शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं को ललितकला शिक्षा के प्रति बेहतर रुझान एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए 686 ललितकला विषय के माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजन करते हुए जिलावार बालिका माध्यमिक विद्यालयों में पद का आवंटन करते हुए पूर्व में नगर निकाय/जिला परिषद् के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई की गयी । पुनः वर्ष 2023 में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु नयी नियमावली, 2023 अधिसूचित की गयी, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के माध्यम से भी ललितकला विषय में नियुक्ति की गयी है ।

उक्त के आलोक में वर्तमान में राज्य सरकार में 498 ललितकला शिक्षक कार्यरत हैं, ललितकला शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार पद सृजन/नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति–2020 उसने इसको लाजिमी किया है, ललितकला शिक्षा को स्कूल के अंदर इसको पढ़ाने के लिए और राज्य के अंदर 9360 माध्यमिक विद्यालय हैं और इनमें से सिर्फ जो हैं लगभग 400 कुछ, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया तो बाकी विद्यालय में क्या ललितकला की पढ़ाई शुरू करने का सरकार इरादा क्यों नहीं रखती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से इनको बताया गया है, स्पष्ट उत्तर है महोदय । हमने कहा है कि हम नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं महोदय, हम जैसे–जैसे आंकलन करेंगे, वैसे–वैसे पद का भी सृजन करेंगे और नियमानुसार जो बहाली की प्रक्रिया है वह भी हमलोग करेंगे, हम इंकार कहां कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार सिंह ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सवाल इंकार का नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब बहुत स्पष्ट हुआ, सरकार तैयार है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपने राज्य के अंदर 9360 माध्यमिक विद्यालय खोल रखे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं । जब 9360 आपके पास विद्यालय हैं तो पद सृजन करने के लिए कहां से आपको अनुमति लेना है, आप तो कर सकते हैं और बच्चों को 2020 नई.....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जो अभी सृजन किया है, वे पद अभी भरे नहीं हैं...

श्री अजय कुमार : सर, मेरी बात को अभी खत्म होने दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अभी तो 498 भरे हैं महोदय और 686 हमने सृजित किया हुआ है तो जो बहाली की प्रक्रिया है उसको हम पूरा कर लेंगे और पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे, पहले ही सृजन करके क्या करेंगे जब हम प्रक्रिया में थोड़ा....

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सर ।

अध्यक्ष : पहले जो पद का सृजन हुआ है उसकी नियुक्ति हो रही है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री सिर्फ इतना है कि आपके पास जो है 8 हजार अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं और आपके पास विद्यालय 9360 हैं तो इस प्रक्रिया को कब तक पूरा करके इसको भर दिया जायेगा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो कहा है कि आकलन कर रहे हैं, अब विद्यार्थी नहीं है वहां हम बहाल करके क्या करेंगे तो आकलन कर रहे हैं, आकलन के हिसाब से माननीय सदस्य को मैंने बताया कि जैसे ही आकलन हो जायेगा वैसे–वैसे हमलोग सीट की भी बढ़ोतरी करेंगे और जो शिक्षक बैठे हैं महोदय उनकी भी नियुक्ति करके उनको भी मौका देंगे ।

टर्न–10 / सुरज / 06.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार सिंह, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री आलोक कुमार सिंह, मुरारी प्रसाद गौतम एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु 36.85 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.15 लाख मीट्रिक टन कम है । उदाहरण स्वरूप रोहतास जिला को धान का कटोरा भी कहा जाता है । इस वर्ष धान क्रय करने का लक्ष्य मात्र 3.15 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है जबकि इस वर्ष रोहतास जिला में 13.35 लाख मीट्रिक धान का उत्पादन हुआ है साथ ही राज्य में धान बेचने हेतु कुल निबंधित 10.20 लाख किसानों में से अब तक मात्र 3.12 लाख किसानों से धान खरीद हुआ है । क्षेत्र के सभी राईस मिलर एवं पैक्स के अध्यक्षों द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि

FRK आपूर्तिकर्ता द्वारा राईस मिल को एफ0आर0के0 नहीं दिया जा रहा है । जिससे पक्सों का सी0एम0आर0/चावल एस0एफ0सी0 को आपूर्ति नहीं हो रहा है।

अतः उपर्युक्त स्थितियों को देखते हुए राज्य का लक्ष्य 45 लाख एम0टी0 करने एवं 31.03.2026 तक धान की अधिप्राप्ति की तिथि विस्तारित करने तथा एफ0आर0के0 के अनुपलब्धता को सुचारू रूप से राईस मिलरों को उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, 01 नवम्बर से धान की खरीदारी राज्य के द्वारा शुरू की गयी । 03 महीने बीत चुके इसके बावजूद भी 1.96 मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई । धान खरीदारी की समय–सीमा सरकार के द्वारा 25 फरवरी तक निर्धारित किया गया है । केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के प्रति चिंतित रहती है । धान की खरीदारी नहीं होने की वजह से आज किसान 18 सौ से 19 सौ रुपया क्विंटल धान बेचने को मजबूर है । सबसे बड़ा उसमें रोड़ा सरकार का सिस्टम है जो हमलोगों को मालूम चला कि धान पहले पैक्स के माध्यम से सरकार खरीदती है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री आलोक कुमार सिंह : उसके बाद उसको पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से मिलर को दिया जाता है और मिलर पुनः चावल एस0एफ0सी0 को देते हैं । एस0एफ0सी0 उसको जमा करती है फिर एफ0सी0आई0 उसको पेमेंट करती है । इसके बावजूद एफ0आर0के0 नहीं मिलने की वजह से आज एक तरफ उद्योग नीति के तहत पूरे बिहार में सरकार चिंतित है और वैसे भी एन0डी0ए0 सरकार में शाहाबाद की स्थिति पिछले साल 22 में से मात्र हमलोग 02 विधायक एन0डी0ए0 गठबंधन से थे और इस बार प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद हम सभी विधायक शाहाबाद के जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो यह सुनने को हमेशा मिलता है क्या विधायक जी....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय पूरा हो गया है । अगली तिथि को इसका उत्तर होगा ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय महोदय, एक मिनट के लिये आग्रह होगा..

अध्यक्ष : समय हो गया है, 12.30 हो गया है ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी से एफ0आर0के0 का जो दो एजेंसी तय हुआ है वह भी जितना उसको मिलता है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे, आगे होगा ।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, 50 रुपये प्रति टन घूस मांगता है...

अध्यक्ष : शेष शून्यकाल की सूचनाएं लिखित उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेज दिये जाए । अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

टर्न–11 / धिरेन्द्र / 06.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा । इसके लिए दिनांक– 06 फरवरी, 2026 एवं 09 फरवरी, 2026 कुल दो दिन निर्धारित है । वाद–विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल चार घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगाः–

भारतीय जनता पार्टी	– 88 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 84 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 25 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 18 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 06 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 05 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 05 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 04 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)(एल॰)	– 02 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट

.....

कुल = 240 मिनट

.....

माननीय सदस्य श्री रजनीश कुमार, अपना पक्ष रखें । आपका 20 मिनट का समय है ।

श्री रजनीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो वर्ष 2026–27 के वार्षिक आय–व्यय बजट पर बोलने की अनुमति दी है उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ । महोदय, बजट किसी सरकार या संस्था का एक वित्तीय रूपरेखा होती है

जिसमें एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक साल के लिए अनुमानित व्यय और प्रस्तावित व्यय का विवरण दिया जाता है । यह दस्तावेज सरकार की या उस बजट, जिस संस्था की बजट होती है उसके नीतियों, प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को दर्शाता है । महोदय, मैं इस सदन में प्रस्तुत राज्य सरकार के बजट वर्ष 2026–27 का स्वागत एवं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, यह बजट जनता की अपेक्षाओं और सरकार की प्रतिबद्धताओं का प्रतिबिंब है । गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के हित को केन्द्र में रखकर यह बजट बिहार के विकास को एक नयी ऊँचाइयों पर ले जाने का संकल्प दिखाता है । महोदय, यह केवल आँकड़ों का दस्तावेज नहीं है । महोदय, वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार के द्वारा बिहार के कमजोर, शोषित, पीड़ित, दिव्यांगों के कल्याण के लिए और उस समय से लगातार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समावेशी विकास की परिकल्पना के आधार पर राज्य में लगातार विकास का काम हो रहा है और इसके लिए हर वर्ष योजना बनाना, उस योजना के लिए संसाधन जुटाना और उस पर पूरी तत्परता के साथ काम कर के बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का लक्ष्य सरकार की रही है । महोदय, वर्ष 2004–05 में हम बात करते हैं तो 23,885 करोड़ रुपये का बजट उस समय होता था, आज लगभग 20 साल के बाद जब इस बजट को रखा गया है तो यह बजट 03 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये लगभग 15 गुना बजट का आकार बढ़ा है । महोदय, लोग कहते हैं कि बजट का केवल साईज बढ़ा लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि बजट का आकार बढ़ने के साथ–साथ महत्वपूर्ण विकास का जो पैमाना है वह बिहार का विकास दर भी लगातार बढ़ा है और वर्ष 2024–25 में, वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर 13.1 परसेंट रिपोर्टिंग हुई है, आयी है जो राष्ट्रीय विकास दर 9.8 परसेंट से भी अधिक है और इस बजट का यह अनुमान है कि जब वर्ष 2025–26 का फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा, वर्ष 2026–27 का यह बजट जब पूरा होगा तो राज्य का विकास दर 13.1 से बढ़कर लगभग 14.9 यानी 15 परसेंट विकास दर हासिल होगा, वर्ष 2027 के अंत में और जो केंद्रीय बजट आयी है केन्द्र सरकार की, उसमें भी अनुमान लगाया गया है कि उसका जब बजट पूरा होगा वर्ष 2026–27 का तो पूरे देश का राष्ट्रीय विकास की जो दर रहेगी वह 10 परसेंट रहेगी जबकि बिहार का 15 परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है । महोदय, यह एक बहुत बड़ी बात है और इससे हम यह कह सकते हैं कि बिहार अब उन राज्यों की श्रेणी में खड़ा है जो देश के आर्थिक विकास में, बिहार सहयोग करने वाला राज्य है और जो राज्य उसके द्वारा देश के सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग होता था उन राज्यों की श्रेणी में अब बिहार भी खड़ा हो गया है । महोदय, यह सरकार की एक बहुत बड़ी, बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

महोदय, मैं दूसरी बात कहूंगा कि विकास दर के साथ–साथ प्रतिव्यक्ति आय भी बिहार का बढ़ा है । किसी राज्य का प्रतिव्यक्ति आय उस राज्य के अंदर विकासात्मक गतिविधियों को करने से, उससे जो सामान्य लोगों को क्या फायदा होता है, इसको मापने का, इसको मेजर करने का, प्रतिव्यक्ति आय एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैरामीटर है और हम प्रतिव्यक्ति आय को अगर देखें तो वर्ष 2005 में प्रतिव्यक्ति आय जहाँ केवल 7,914 रुपया था वही वर्ष 2024–25 में यह बढ़कर 76,490 रुपया हो गया है और यह कोई अचानक नहीं बढ़ा, यह हम अगर पिछले दो–तीन साल का भी आँकड़ा सदन के सामने रखें तो वर्ष 2022–23 में 60,573 रुपया, वर्ष 2023–24 में 68,624 रुपया, वर्ष 2024–25 में जैसा कि हमने कहा कि 76,490 रुपया । महोदय, यह संकेतक है कि राज्य में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और उस विकास का सकारात्मक प्रभाव बिहार के आम जनमानस पर पड़ रहा है और उसका लाभ सब लोगों को मिल रहा है ।

महोदय, मैं एक तीसरी बात कहूँगा जो बजट का पैरामीटर होता है और विकास का पैमाना और जिसकी चर्चा हम करते हैं कि महंगाई दर । हमारे बजट बनाने का और उस बजट पर बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके काम करने के तरीके से बिहार में महंगाई दर भी नियंत्रण में रहा है । अगर महंगाई दर की बात जब हम करते हैं तो ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स को देखते हैं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है और उसके अनुसार वर्ष 2025 में जहाँ देश की महंगाई दर 3.5 से 4 प्रतिशत रहा, वहीं बिहार की महंगाई दर सिर्फ 01 प्रतिशत रहा है और इसके कारण गरीब लोग और जो आम लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको जीवनयापन में सुविधा मिली है । महंगाई बहुत नहीं बढ़ी, महंगाई नियंत्रण में रही इसका भी लाभ मिला है और यह ऐसे नहीं हुआ है महोदय, जो मैंने तीन पैरामीटर बताये प्रतिव्यक्ति आय, विकास दर और नियंत्रित महंगाई दर, यह बिहार में ठोस वित्तीय अनुशासन, जो गुड गवर्नेंस का, सुशासन का एक मजबूत आधार है, उसके कारण ये तीन उपलब्धियां हुई हैं और यह सरकार जिस तरह से वित्तीय अनुशासन में काम कर रही है, उसी का यह परिणाम है ।

महोदय, अब बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, महोदय, मैं एक बार सदन में यह भी चर्चा करूंगा कि पहले 15 साल उनके जमाने में कैसे बजट बनता था और आज कैसे बजट बन रहा है और यह जो बजटीय सुधार हुआ है, यह भी हमारी सरकार, एन॰डी॰ए॰ की सरकार ने किया है । पहले दो बार में बजट बनता था, एक बार मार्च में लेखानुदान लाते थे विधान सभा के अंदर और जितना खर्चा इनको करना था उस खर्चा को पास करा लेते थे और बाद में जुलाई–अगस्त में जाकर के बचे आठ महीने के लिए एक बजट लाकर उसकी खानापूर्ति की जाती थी ।

(व्यवधान)

अभी नहीं होता है । अब सुनिये । महोदय, लेखानुदान पास करने का अधिकार राज्य सरकार को है, संवैधानिक अधिकार है लेकिन संविधान में यह व्यवस्था है कि लेखानुदान विशेष परिस्थिति में ही लाया जा सकता है । राज्य में जब चुनाव हो, राज्य में कोई ऐसी विशेष बात हो तभी संविधान प्रदत्त उस अधिकार का उपयोग राज्य सरकार करती है और लेखानुदान लाती है । संवैधानिक व्यवस्था यह है कि पूरे एक साल के लिए अप्रील से अगले मार्च तक के लिए बजट मार्च में एक महीना पहले लाया जाय । अध्यक्ष महोदय, इस परंपरा की शुरूआत अगर हुई, उस लेखानुदान ला कर के और एक अनियंत्रित बजट बनाने की बात, खानापूर्ति बजट बनाने की बात को समाप्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार वर्ष 2006 में की ।

....क्रमशः....

टर्न–12 / अंजली / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री रजनीश कुमार : महोदय, जब वर्ष 2006 में पहला बजट बन रहा था एन0डी0ए0 का, तो उसमें जो सुधार हुआ, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं । पूरे 12 महीने का बजट बनाना और उसके पहिले एफ0आर0बी0एम0 एक्ट पास किया गया बिहार में –Fiscal Responsibility and Budget management act, 2006 लागू किया। महोदय, यह इसलिए लागू करना था कि बजट को एक संवैधानिक रूप से तैयार किया जाय और जो बजटीय अनुशासन है, वित्तीय अनुशासन है वह बजट पर लागू रहे । इसके लिए एफ0आर0बी0एम0 एक्ट को लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया और यह उस समय किया जब पहली बार एन0डी0ए0 की सरकार बनी, 2005 नवंबर के बाद और वर्ष 2006–2007 का, जब पूरे एक साल का बजट बन रहा था, तो उस बजट को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया और एफ0आर0बी0एम0 एक्ट जैसा कि मैंने आपको कहा, उसको लागू करना, एक साल, पूरे बारह महीने का बजट बनाना, यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई । अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या हुआ, पहले क्या होता था, अभी मार्च का महीना आने वाला है, पूरे बिहार में, उस समय मार्च के महीने में, अखबाारों में छपता था, मार्च लूट की कहानी छपती थी, ट्रेजरी में मार्च के अंतिम सप्ताह में ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों के गठजोड़ से और दलालों के द्वारा वहां भीड़ लगी रहती थी और पूरा पैसा मार्च के महीने में अंतिम सप्ताह में निकाल लिया जाता था, यह उस समय के मीडिया में जो पुराने लोग हैं अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखिए । शांति–शांति ।

श्री रजनीश कुमार : सुनिये–सुनिये । और यह मार्च लूट की परिपाटी बंद हो गई ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के नहीं बोलें । आप बोलिये ।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह मार्च लूट की परिपाटी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शोरगुल नहीं करें ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, अभी तो बहुत कुछ इनको सुनना पड़ेगा, धैर्य रखें । मार्च लूट की परिपाटी अब कहां है ? वर्ष 2006–07 के बाद से अब मार्च लूट की परिपाटी खत्म हो गई और यह इस बात का संकेत है कि बिहार की कुर्सी पर एक ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उनको सुरक्षित रखना आता है और सरकार उसको जनकल्याण के लिए खर्च कर रही है, वह लूट ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों के बीच में नहीं जा रहा है, यह हमारी सरकार ने किया । महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये आर्थिक सर्वेक्षण जो निकला, बजट के एक दिन पहले जो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य गुप्ता जी, बिना अनुमति के नहीं बोलिए ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, बजट आने के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, ये आर्थिक सर्वेक्षण लाने की भी परिपाटी की शुरुआत वर्ष 2006–07 से हमारी सरकार ने किया है, वर्ष 2006–07 से लाने का काम किया । पहले आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आता था । महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण आप उसको देखिए, उसमें जो आंकड़े हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, क्या उपलब्धि है, हम आज इस बजट को पास कर रहे हैं, उस बजट का क्या इंपैक्ट हुआ और सोशल इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म पर पूरे बिहार के हर चीज को, आंकड़े को उसमें दर्शाया गया है, यह पहले नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि जो सरकार थी उस समय उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे आर्थिक सर्वेक्षण जैसे आंकड़ों को सार्वजनिक कर सकें, जनता के सामने ला सकें, यह लाने की हिम्मत उनको नहीं थी, यह काम बिहार की सरकार ने किया और जो आंकड़े हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, विकास के पैमाने पर जो उपलब्धियां हुई हैं, हम जहां तक पहुंचे हैं,, उसको जनता के सामने, मीडिया के सामने, देश और दुनिया के सामने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रकाशित करने का अगर हिम्मत हुई है तो वह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार को हुआ है और वह काम हम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय । महोदय, आज जब हम बात कर रहे हैं वर्ष 2006–07 से, तो लगातार बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और एन0डी0ए0 की सरकार के प्रयासों और उनके संकल्पों के कारण आज बढ़ रहा है, एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार आज बिहार में है । महोदय, चर्चा कर रहे थे, उधर से खड़ा होकर बोल रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ॰ श्री कृष्ण सिंह जी के बाद लगभग 29–30 साल, 1961 से 1990 के बीच में इन 29 वर्षों में

बिहार के 23 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, 23 मुख्यमंत्री हुए । तीन दिन, पांच दिन से लेकर और अधिकतम तीन साल के मुख्यमंत्री बनते रहें और किसी को बिहार की चिंता नहीं थी कि बिहार को कैसे हम आगे बढ़ावें और उसके बाद वर्ष 1990 के बाद जो सरकार आई, वर्ष 1990 से 2005 तक जिस 15 साल की बात हम करते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए मित्र उनको तकलीफ होती है, लेकिन पूरा देश–दुनिया गवाह है, संपूर्ण बिहार गवाह है कि उन 15 सालों में बिहार का विकास नहीं हुआ, जो कुछ भी काम पूर्व में हुआ था उसको भी समाप्त करने का काम उस समय की सरकार ने करने का काम किया था ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोल रहा हूं इसलिए मुझे यह बताना जरूरी है कि बिहार ने जो उपलब्धि हासिल की है, पूरी तरह से गड्ढे में गया हुआ एक संस्था, एक राज्य अगर आज इस लेवल तक पहुंचा है, उसकी यात्रा बड़ी कहानी है मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा ।

(व्यवधान)

अभ्यास हो जाएगा धीरे–धीरे आप चिंता मत करिए । आप सुनिये । अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं बिहार विधान परिषद् में सदस्य रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, बिहार एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य है । देश के जितने भी राज्य हैं उसमें बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो रेवेन्यू सरप्लस राजस्व अधिशेष राज्य है । राजस्व अधिशेष का मतलब यह है कि हमारा एफ0आर0बी0एम0 एक्ट भी कहता है और जितने भी केंद्रीय वित्त आयोग हुए, राज्य वित्त आयोग की भी, यह हमेशा एक डिसिप्लिन रहा कि राज्यों को अपना अधिशेष होना चाहिए, राजस्व अधिशेष होना चाहिए, मतलब जितना हमारा राजस्व आय है, हम उसके अंदर राजस्व व्यय को करें और उसी खर्चे से करें और यह आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार राजस्व अधिशेष राज्य है, इसका यह मतलब है सीधा कि राज्य के जो रेगुलर खर्चे हैं, सैलरी है, वेतन जिसको कहते हैं, पेंशन है, ब्याज है, सब्सिडी है ऐसे जो रेगुलर खर्चे हैं, उसको करने के लिए सरकार को अब ऋण नहीं लेना पड़ता है, अब ऋण लेकर, कर्ज लेकर हमको सैलरी, हमको वेतन पे नहीं करना पड़ता है, यह राज्य के विकास की एक बड़ी कहानी है । यह बहुत बड़ी बात है कि अब ऐसे खर्च को करने के लिए हम कर्ज नहीं लेते हैं अध्यक्ष महोदय । एक समय था जब वेतन का भुगतान करने के लिए यह सरकार गवाह है और बैठे हुए लोग हैं, उल्टा करके देखें उस बजट के इतिहास को, उस समय के आर्थिक विवरण को, तो आपको पता लगेगा कि सैलरी के लिए, कर्ज के लिए, वेतन भुगतान करने के लिए कितने महीने लगते थे और वह भी पैसा लोन लेकर के आता था, कर्ज लेकर वेतन का भुगतान किया जाता था लेकिन आज वेतन का बोझ जरूर बढ़ा है, बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जितनी बहाली की है सरकारी क्षेत्र में, शिक्षकों की बहाली हुई, नर्स की बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई, अमीन की बहाली हुई एक बहुत बड़ी संख्या है, इसके कारण वेतन का बोझ सरकार का

बढ़ा लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इतना वेतन बढ़ने के बाद भी हम अपने राजस्व इनकम से ही अपने वेतन, अपने पेंशन और इत्यादि रेगुलर खर्चों का हम वहन कर रहे हैं, हाँ, सरकार जो ऋण ले रही है वह ऋण ले रही है, वह ऋण पूंजीगत खर्चे के लिए इफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के करने के लिए ले रही है, अब वेतन के लिए ऋण नहीं लेना पड़ता है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा आप समझते हैं कि सदन में यह बात भी आप सब को मालूम होगी कि लगातार बिहार राजकोषीय घाटा को मेंटेन रखा है और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है 16वें वित्त आयोग का कि राजकोषीय घाटा 3 परसेंट जी0एस0डी0पी0 का होना चाहिए, अपने बिहार में वह 2.99 प्रतिशत जी0एस0डी0पी0 का है और इसका राजकोषीय घाटा भी ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के विकास को गति देने के लिए, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, साथ में 2014 से ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति जिस तरह का सहयोग रहा है वह भी मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं । हमें केंद्र से आज दो तरह से पैसे मिलते हैं, मूलतः एक तो केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी, लगातार बिहार की हिस्सेदारी बढ़ रही है और केंद्र से करों में जो हिस्सा बिहार को मिलता है इस बार वर्ष 2026–2027 में 1 लाख 58 हजार 178 करोड़ रुपया अनुमानित है । महोदय, केंद्रीय अनुदान के रूप में जो सहयोग मिलता है वह 51 हजार 896 करोड़ है, कुल सहयोग 2 लाख 10 हजार 74 करोड़ अनुमानित है, यह हमारे बजट में केंद्र से प्राप्त होगा, यह बहुत बड़ा सहयोग केंद्र के द्वारा बिहार के विकास के लिए किया जा रहा है और वर्ष 2025–2026...

(व्यवधान)

मनरेगा में भी बजट बढ़ा है । मनरेगा में भी बढ़ा है । आपको बाद में बतायेंगे।

(क्रमशः)

टर्न–13 / पुलकित / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री रजनीश कुमार : वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी, जो पिछला वित्त वर्ष था, उसमें भी 1,43,069 करोड़ केंद्रीय करों का और 54,758 करोड़ का केंद्रीय अनुदान कुल 1,97,827 करोड़ और इस साल पिछले साल की तुलना में 13,000 करोड़ ज्यादा मिलने का अनुमान बजट में है । कल नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे थे । विशेष राज्य का दर्जा के लिए चलिए सब मांग करते हैं । आप तो 15 साल वहाँ बैठे हुए रहे इस तरफ, और 15 साल आपकी सरकार रही । उस समय तो केंद्र में कमजोर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की परिपाटी थी । लेकिन आपने तो एक बार भी जाकर विशेष राज्य का दर्जा की

मांग नहीं की । आप पता करिए, बिहार के सामने आज कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है, कोई मीडिया में खबर नहीं है, आपने मांगा ही नहीं, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और आज आप बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शांति बनाये रखिये, प्लीज ।

श्री रजनीश कुमार : अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत भी नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज दिया और अभी हमने आपको कहा कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपया...

(व्यवधान)

केंद्र की सरकार ने, मैं पुनः कह रहा हूँ कि 2 लाख करोड़ रुपया लगभग पिछली बार भी दिया और इस बार भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इस बार भी बिहार को सहयोग के रूप में दे रही है । महोदय, इतना ही नहीं, पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र हर साल लगभग 10,000 करोड़ की राशि इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दे रही है । महोदय, यह काम 2022–23 से लगातार हो रहा है और बिहार को इसमें भी इसका हिस्सा मिलता है । महोदय, अभी केंद्रीय बजट में इस फंड के लिए जिससे राज्यों के पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है केंद्रीय बजट में, और उसमें बिहार का भी हिस्सा महोदय 10 से 15 हजार करोड़ रुपया है और वह अनुमानित है कि वह मिलेगा ।

महोदय, बजट में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने के लिए जो काम यहाँ पर हुआ है माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्राथमिकता का क्षेत्र चयन किया गया है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं कानून व्यवस्था पर सरकार ने देश के अन्य राज्यों के औसत खर्च से ज्यादा खर्च करने का निर्णय लिया है । अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डेटा है । शिक्षा में इस बार बजट का 21.7 प्रतिशत जबकि अन्य राज्यों का औसत मात्र 14.3 प्रतिशत खर्च का है। उसी तरह स्वास्थ्य में महोदय, स्वास्थ्य पर 6.3 प्रतिशत जबकि अन्य राज्यों का 6.2 प्रतिशत मात्र है । ग्रामीण विकास पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमने अपने बजट का एलोकेशन 9.4 प्रतिशत रखा है जबकि अन्य राज्यों में ग्रामीण विकास विभाग पर यह औसतन 4.8 प्रतिशत बजट का खर्च होता है । पुलिस और कानून व्यवस्था पर हमने 5.2 प्रतिशत रखा है जबकि अन्य राज्य इस पर 3.9 प्रतिशत खर्च करते हैं । यह हमारी प्राथमिकता में है और ये प्राथमिकताएं बिहार की जो स्थिति है, बिहार के लिए है, जिससे बिहार और मजबूती से विकास आगे करेगा। महोदय, इस आधार पर विभाग में बजट का एलोकेशन हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब अपना भाषण संक्षिप्त करें । आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दो–तीन मिनट और दिया जाए । महोदय, 1 करोड़ 56 लाख जीविका दीदी को 10 हजार, अच्छा काम करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका प्रावधान है 2 लाख रुपया मिलेगा । 125 यूनिट बिजली फ्री है । 400 से बढ़कर 1100 पेंशन हुई । जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सरकार अब केंद्र की तर्ज पर 3000 रुपये किसान के खाते में देगी । बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराएगी । महोदय, 2025–2030 के लिए सात निश्चय पार्ट–3 शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत भी प्रति व्यक्ति के आय को 5 साल में दोगुना करने का एक लक्ष्य रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, 2020–2025 तक युवाओं को 50 लाख नौकरी दी गयी, अब अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है । राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए काम किया जा रहा है और उसके लिए 50 लाख करोड़ की निजी निवेश का एक लक्ष्य है । इसी तरह कृषि रोड मैप बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से लगातार उस पर काम कर रहे हैं, इस बार जो कृषि रोड मैप है 2024 में बना वह 2029 तक है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, प्रखंड में डिग्री कॉलेज, सुलभ स्वास्थ्य की व्यवस्था, इस तरह बहुत सारे काम हुए हैं । महोदय, समय कम है इसलिए मैं सिर्फ अंत में यह कहकर एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ । कल बहुत सारी बातें हो रही थी । मैं तो यही कहूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए महोदय,

कि वे आरोपों की दीवार बनाते रह गए,
आप आरोपों की दीवार बनाते रह गए,
हम विकास की इमारत खड़ी करते चले गये ।
वे वादों की किताब लिखते रह गए,
हम हर पन्ने को हकीकत में बदलते चले गए।।

महोदय, कल बाज की बात हो रही थी । सदन में बाज की उड़ान का जिक्र हुआ । महोदय अब समाप्त कर रहे हैं । महोदय, इतिहास गवाह है कि बाज बनने के लिए सिर्फ सपना नहीं, दूरदृष्टि, साहस और निरंतर परिश्रम चाहिए जो शब्दों से नहीं उपलब्धियों से साबित होता है ।

ऊंचाइयों पर पहुँचना बड़ी बात नहीं है,
ऊंचाइयों पर पहुँचना बड़ी बात नहीं है,
वहाँ टिके रहना असली चुनौती है।।

महोदय, अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं कुछ सेकेंड दिया जाए । महोदय, 20–25 साल तक लगातार अपने मेहनत और परिश्रम से जनता के भरोसे पर

खरा उतरते हुए, यह मामूली बात नहीं है । हम सबको गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास पुरुष के रूप में यह कीर्तिमान स्थापित किया है, उस ऊंचाई पर खड़े रहे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ सिंह ।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत श्री सुशील कुमार मोदी जी को भी याद करता हूँ, जिनके प्रयासों से बिहार ने इस ऊंचाई को छुआ । एक लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला । महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपके प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं इस 2026–2027 के इस बजट का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद, जय हिन्द ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ सिंह ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

अध्यक्ष : आपका समय 10 मिनट है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और करगहर विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से दोबारा चुनाव जीत कर आया हूँ । मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपने नेता के चरणों में नमन करता हूँ ।

महोदय, जब से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता आई है, तब से लेकर आज तक लगातार विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है । आज बिहार का जो हमारा बजट है, 3,47,589.76 करोड़ है । जबकि मुझे याद है कि जब 20 साल पहले जिन लोगों की सरकार थी, उस समय का बजट मात्र 24 हजार करोड़ हुआ करता था । धरती और आसमान का फर्क हो गया है ।

हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी दिन–रात बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करते हैं । पहले के लोग केवल सत्ता में बैठकर बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए थे । बजट जो आया है, उस बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर बजट का खर्च होना है । 60,204.61 यह मामूली बजट नहीं है और शिक्षा पर इसलिए बजट ज्यादा हुआ है कि शिक्षा समाज का अनमोल रत्न है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है ।

बिहार में उस समय मुझे याद है कि किसी गाँव में जाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यालय नहीं हुआ करता था । जो शिक्षा के मंदिर के रूप में देखने के लिए बच्चे और गार्जियन ललायित रहते थे, उस समय कोई काम पहले की सरकार नहीं कर रही थी । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा में बजट बढ़ाकर हर गाँव में विद्यालय खोलने का काम किया । महोदय, वे जो विद्यालय खुले हैं, जब गाँव के रास्ते से हम लोग चलते हैं, तो पिंक कलर का

जो भवन दिखता है, उससे स्पष्ट पता चल जाता है कि यह इस गाँव का शिक्षा का मंदिर है यानी विद्यालय है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह बिहार सरकार की उपलब्धि है ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / हेमन्त / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, पोशाक की राशि, साइकिल की राशि यह तमाम तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाईं जिसमें दलित, गरीब, शोषित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा के जो बच्चियां पांच, छः क्लास के बाद आगे नहीं बढ़ पाती थीं, उनके मन में और जुनून पैदा करने के लिए साइकिल की योजना चला कर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया और आज बिहार में बच्चों के साथ–साथ बच्चियों की जो संख्या है, विद्यालय में ज्यादा दिख रही है। बच्चियां उड़ान लगा रही हैं। साइकिल से जाती हैं और जब मैट्रिक के रिजल्ट की बात आती है, तो बिहार की बच्चियां अव्वल स्थान पर जाती हैं।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

इंटर तक की पढ़ाई, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने इंटर तक की पढ़ाई एक पंचायत से गांव से शुरू कराने का काम किया। जितने उच्च विद्यालय थे, सभी उच्च विद्यालय को 10 प्लस टू करने का काम किया और आज गरीब, दलित, शोषित के बच्चे और बच्चियां अपने गांव से जाकर इंटर तक की पढ़ाई करती हैं। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुआ है कि जहां भी जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे ताकि बच्चों को कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़ने के लिए ये परेशानी नहीं उठानी पड़े। यह हमारी सरकार का दूरदर्शी इरादा है, महोदय। आप देख लीजिए सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आईटीआई कॉलेज खुला, बी एड कॉलेज खुला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार चाहती है कि बिहार का बच्चा पढ़–लिख कर बिहार का नाम रौशन करे और देश में अव्वल स्थान खड़ा करे इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, महोदय। जबकि पिछली सरकार की सोच, विजन जो था वो बिल्कुल इस तरह का नहीं था। उस समय उस जमाने में वो लोग चरवाहा विद्यालय खोला करते थे, महोदय, और बिहार के बच्चे और बच्चियों को चरवाहा बनाना चाहते थे और हमारी सरकार बिहार के बच्चों और बच्चियों को डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े–बड़े अधिकारी बनाना चाहती है। आज बजट के सवाल पर अगर बात की जाए, महोदय, तो गरीब के बच्चे, पढ़ने के लिए पैसे के अभाव में कुछ लोग परेशानी से बैठ जाते थे, नहीं पढ़ पाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू करके गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आज बिहार के बच्चे नौकरी में भी आगे जा रहे हैं।

महोदय, अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें, तो ग्रामीण विकास का भी बजट अगर हम देखते हैं, तो 23,701.18 हजार करोड़ है सर। अब बताया जाए कि लोग कहते हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहा है। जीविका के माध्यम से, उन महिलाओं को, जिनको 500 रूपये के लिए, 100 रूपये के लिए परेशानी होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए रास्ता निकालने का काम किया और विकास दर बढ़ाने का काम किया। जब सरकार ने 10,000 रूपये की घोषणा की कि सभी गांव की एक–एक दीदियों को हर घर में 10,000 रूपये देंगे, तो ये जो लोग हैं, ये जा कर गुमराह कर रहे थे कि जो पैसा आएगा, इस पैसा को लौटाना पड़ेगा। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इस सदन को कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, वही करते हैं। मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में मेल है। आपकी वाली बात नहीं है कि कह कर निकल गए, काम कुछ करना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कई तरह की सरकार ने हमारी काम की, 10,000 रूपया तो गया, लेकिन यह भी घोषणा है कि जो महिलाएं 10,000 रूपया लेकर उद्योग लगाएंगी, काम करेंगी, उन महिलाओं को दो–दो लाख रूपया हमारी सरकार देने का काम करेगी। यह हमारी सरकार की सोच है और उसकी बजट की व्यवस्था की गई है। यह नहीं कि घोषणा कर दी गयी और सरकार के पास बजट नहीं है। पहले बजट हमारे यहां फिक्स होता है, इसके बाद प्रारूप बना कर हम लोग की सरकार काम करती है। महोदय, मनरेगा की बात कर रहे हैं। मनरेगा में भी, हम लोग भी पंचायती राज में जिला परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मनरेगा में काम चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब विपक्ष के लोगों को आंख से दिख नहीं रहा है, उसमें सरकार का क्या कसूर है ? देखने की जरूरत है।

महोदय, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए। महोदय, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोलें।

श्री बशिष्ठ सिंह : तो 21,270.41 करोड़ स्वास्थ्य विभाग का बजट दिया गया है। ये लोग बोल रहे हैं। महोदय, मुझे याद है कि जब हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, तो अस्पताल में जाते थे, तो न सुई रहती थी, न रुई रहती थी, डॉक्टर की बात तो दूर है, डॉक्टर के कुर्सी पर कुत्ता बैठा हुआ करता था,...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें।

श्री बशिष्ठ सिंह : और आज की सरकार में सुई भी है, रुई भी है, ये सारी व्यवस्था है, महोदय। ये लोग क्या बात करेंगे? यह लोग क्या बात करेंगे, महोदय। यह सारी व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है सर। ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा है, महोदय।

उपाध्यक्ष : शांति बनाए।

श्री बशिष्ठ सिंह : ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा है, महोदय। सारे काम हमारी सरकार कर रही है, महोदय। और बोलते हैं कि कुछ नहीं है। गृह विभाग का भी बजट हम देख रहे हैं, तो 20,132.37 करोड़ गृह विभाग का बजट है। महोदय, पहले के लोग तो थाना में जाते थे किसी कारणवश लड़ाई–झगड़ा में अपनी अर्जी लेकर, तो लोग लिखते भी नहीं थे। आज कम–से–कम यह सच्चाई है कि गरीब–से–गरीब कोई जाता है तो उनकी एफ0आई0आर0 लिखी जाती है और उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होती है, कानूनी रूप से कार्रवाई होती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपको जब वक्त मिलेगा, अपनी बात रखिएगा।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, पहले के राज में 814 थाना हुआ करते थे, आज बढ़ कर 1380 थाना हो गये। आज 112 पर डायल कीजिए, 112 पर डायल कीजिए और पुलिस तुरंत पहुंचती है और जा कर...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास 1 मिनट का वक्त है।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, मैं आपको बताता हूं कि विकास की दर 13.1 इस बिहार में हो रही है और इन लोगों परेशानी हो रही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखिये।

श्री बशिष्ठ सिंह : हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में काम किया है। बिहार सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किया है। तभी तो 20 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार की जनता के अंदर एंटी इनकंबेंसी नहीं गया और भारी बहुमत से फिर आदरणीय नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यह गवाह है, बिहार की जनता ने गलत लोगों को किनारे कर दिया और काम करने वाले को सत्ता दी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाए रखिये।

श्री बशिष्ठ सिंह : कि जाइये बिहार में अमन, चैन, शांति बरकरार रहेगी और बिहार का विकास होता रहेगा। ये हम बताना चाहते हैं। महोदय, बजट में इन लोगों के राज में छः–छः महीना, एक–एक साल कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता था।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है।

श्री बशिष्ठ सिंह : और कर्मचारियों को उन लोगों के समय में पैसा नहीं मिलता था। आज के समय में ये कोई नहीं कहने वाला है कि हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। टाइम

टू टाइम वेतन मिलता है। इसलिए महोदय, मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूं..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन ग्रहण करें।

श्री बशिष्ठ सिंह : कि आपने समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। सरकार के प्रति, जो बजट आया है उसका समर्थन करता हूं और आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने जो बजट वर्ष 2026–27 के लिए सदन में प्रस्तुत किया है और आसन से मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर अपनी राय रखने का अवसर दिया गया। मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और एनडीए के तमाम नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पर मुझे अपनी राय रखने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट किसी भी सरकार की कार्य योजनाओं की प्राथमिकताएं होती हैं और प्रतिवर्ष यह बजट इस सदन में आता है। पहले भी आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि एनडीए शासन जब से बिहार में आया, तब से जो बजट बनाया गया है, जो लाया गया है, उस बजट में प्राथमिकताएं क्या हैं? योजना व्यय की स्थिति क्या है ? और पहले 2005 के पहले जो सरकार 15 वर्षों तक बिहार में थी, उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं ? और उनका प्लान और नॉन–प्लान का डिफरेंस क्या था ? महोदय, मैं कुछ ही देर पहले जब एक देख रहा था तो मैंने देखा कि वर्ष 2005 जो इनका आखिरी, हमेशा–हमेशा के लिए, राजद शासन काल का आखिरी काल था, जो फिर बिहार में कभी लौटने वाला नहीं है। उसमें इनकी योजना का आकार टोटल 3000 करोड़ के बजट में सिर्फ और सिर्फ 15 प्रतिशत का था।

(क्रमशः)

टर्न–15 / संगीता / 06.02.2026

श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्रमशः) : उपाध्यक्ष महोदय, उन दिनों, मैं सुन रहा था, हमारे सामने से मित्र बोल रहे थे कि जरा बताइए प्रति व्यक्ति आय क्या है तो मैं ही बता देता हूं अध्यक्ष महोदय, राजद के शासनकाल का जो अंतिम बजट था, उस समय 7 हजार 914 रुपये प्रति व्यक्ति आय बिहार में था और अगर हम 24–25 के प्रति व्यक्ति आय को देखें तो 69 हजार 321 रुपये प्रति व्यक्ति है, यही अंतर है, यह जानिए और सीखिए। अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें । माननीय सदस्य आप बैठ जायें ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आज हमें फख्र हो रहा है कि एन0डी0ए0 की सरकार ने 23 हजार 885 करोड़ रुपये के बजट से...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं । कृपया शांति बनाएं ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : बिहार के विकास का जो जिम्मा अपने पास लिया, औसत 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के विधि के साथ यह आंकड़ा आज के दिन में 3 लाख 47 हजार 589. 76 करोड़ रुपये का है । आज अगर हम देखते हैं तो हमारा प्लान हेड का एक्सपेंसेज 35 प्रतिशत है । जहां राजद के शासनकाल में 15 प्रतिशत प्लान हेड, नॉन प्लान 85 था, इस बजट की खुबसूरती है कि आज 35 प्रतिशत हमारा प्लान हेड में हुआ, 65 प्रतिशत नॉन प्लान इसलिए है कि हमने रिक्तियों में बहालियां की हैं । हमने कार्यालयों में कार्यबल बढ़ाया है, यह माननीय नीतीश कुमार और उनके मंत्रिपरिषद् की कार्ययोजना का नमूना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, 2024–25 की तुलना में इस वर्ष का जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र यादव जी के द्वारा लाया गया तो अपने ही बजट के आकार के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 30 हजार 694 करोड़ रुपये का अत्यधिक का बजट आया है और ठीक कहा है कि शिक्षित बिहार का जो संकल्प आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, विकसित बिहार का संकल्प जो आदरणीय नीतीश कुमार का है, समाज के हर तबके, युवाओं के कल्याण का जो लक्ष्य नीतीश कुमार जी का है, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए शिक्षा में अप्रत्याशित ढंग से 68 हजार 216.95 करोड़ रुपये का पहले भी इस पर चर्चा हुई है, मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ग्रामीण विकास में, ऊर्जा के क्षेत्र में, नगर विकास में, ग्रामीण कार्य में पंचायती राज, जो हमारा एक पंचायत सरकार के रूप में काम कर रहा है, समाज कल्याण जो लोगों के हित में काम कर रहा है, इन सभी पर काम करते हुए महिला सशक्तीकरण का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार की सरकार ने देश में पहली बार यह योजना लायी कि महिलाओं को 10 हजार रुपया दिया गया जिससे वे अपने कामकाज का चयन करें और जैसे–जैसे उनके विकास, उनके व्यापार का विकास होगा, दो लाख रुपये तक की राशि इसलिए उन्हें मिलेगा कि महिलाएं सशक्त हों और समृद्ध भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार का जो लक्ष्य है कि बिहार देश में ऐसा राज्य बने जो सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को हासिल करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य और अहम् योगदान दें । हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को हासिल करते हुए बढ़ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम अगर बात करें आधारभूत संरचना का तो नीतीश कुमार जी के सरकार के कार्य और उपलब्धियों के आधार पर केंद्र ने जिस तरह

से बिहार को विशेष पैकेज दिया है, बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेल यातायात की सुविधाएं बढ़ रही हैं और हवाई यातायात के साथ–साथ अब तो जलमार्ग में भी केंद्र के सहयोग से जो योजनाएं आयी हैं, बिहार के सर्वांगीण विकास के मार्ग को रोक नहीं सकता । उपाध्यक्ष जी, हम अगर बात करें युवाओं के संबंध में तो प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान का निर्माण होगा । किसानों के लिए 200 प्रखंडों में सरकारी आउटलेट खोलकर उनके आय को बढ़ाने की योजना बनी है और बिहार के युवाओं को बेरोजगारों को एम0एस0एम0ई0 के जरिए आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराकर, औद्योगिक प्रांगण विकसित कर, सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यबल का गठन कर बेरोजगारी को दूर करने, बिहार के आय को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार निरंतर काम कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग कहते थे कि बजट से बिहार को क्या मिला, मैं उनको कहना चाहता हूं केंद्र के बजट से हो, बिहार के बजट से हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है लेकिन 2005 तक जो सरकार बिहार में चल रही थी वह परिवार के विकास का काम करती थी, बिहारवासियों की चिंता उनको थी ही नहीं और वे चर्चा करते हैं बिहार के बजट पर, मैं तो कहता हूं दो प्रतिशत भी उनको बिहारवासियों के प्रति प्रेम है तो वे सीधा–सीधा इस बजट के समर्थन में आएं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार जिस तरह से विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करने में लगी है वह भी बिहारवासियों के सामने सरकार का समर्थन करके इस बजट का समर्थन करें तब समझ में आएगा कि उनके मन में भी बिहार के प्रति चिन्ता है, प्रेम है, मोहब्बत है और विकसित बिहार वे बनाना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिहार में क्या था पहले, लालटेन और डिबरी में हम पढ़ते थे, हमलोग पढ़े हुए हैं लेकिन आज बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराना क्या इस सरकार की उपलब्धियों का ऐतिहासकि पहलू नहीं माना जाएगा । महोदय, बिहार के विकास में जो हुआ, आज कम से कम...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाएं । कृपया शांति बनाएं ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : बिहार के बारे में यह तो चर्चा नहीं होती कि बिहार के बजट में ऐसे सेंध लगे हुए हैं जो रोड का अलकतरा किसी के पेट में चला जाए, यह चर्चा तो नहीं होती है । आज बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि दुनिया मानने लगी है कि भारत के विकास में बिहार का विकास अहम् योगदान दिया है और हम सभी स्तर पर बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और सदन से यह निवेदन करता हूं कि सर्वसम्मत इस बजट का समर्थन करके बिहार में ऐतिहासिक फैसला इस सदन का हो, ऐतिहासिक संदेश जाए

और बिहार के विकास के लिए जो रोड मैप है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उस रोड मैप पर बिहार को चलने में विपक्ष का भी सहयोग मिले । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी । आपके पास दो मिनट का वक्त है ।

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में जो आंकड़ों की हवाबाजी है, जो लिफाफाबाजी है उसके लिए एक मुहावरा है–थोथा चना बाजे घना । सबसे पहले हम कहेंगे कि जो बजट के अंदर सी0ए0जी0 ने जो कहा था कि 70 हजार 877 करोड़ रुपये का बिहार सरकार ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं जमा किया, इसका तो कोई जिक्र माननीय मंत्री जी के अभिभाषण में भी नहीं था, बजट में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है । 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला है, उस पर बात होनी चाहिए । बजट में जो जी0एस0डी0पी0 का ऋण दिखाया गया है, वह 35 प्रतिशत है । सरकार आमतौर पर दंभ भरती है कि डबल इंजन की सरकार है, जबसे सरकार बनी है तबसे रफ्तार कुछ बढ़ा है ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / यानपति / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, 2013–14 में जो स्टेट का जी0डी0पी0 था उसका 27.42 प्रतिशत ऋण था आज बढ़कर के वह 34.09 प्रतिशत हो गया है । मामला केवल परसेंटेज का नहीं है अगर रुपये में देखा जाय तो 86939 करोड़ रुपये से बढ़कर के आज बिहार के जी0डी0पी0 के ऊपर 4 लाख 46 हजार 326 करोड़ रुपये का ऋण है, यह बजट में दिख रहा है और आंकड़ों की जो हवाबाजी इसमें किया गया है आमतौर पर आंकड़े को, जी0डी0पी0 को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाने के लिए प्रति व्यक्ति जो जी0डी0पी0 होता है उसको सरकार छिपा लेती है । अभी माननीय महोदय सही कह रहे थे कि बिहार में अभी प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 जो है वह 68624 रुपया है लेकिन राष्ट्रीय औसत आज का क्या है महोदय, एक लाख 88 हजार 892 रुपये राष्ट्रीय औसत है। एक तिहाई भी हमलोग नहीं हैं बिहार और यहां तक कि बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां प्रति व्यक्ति जो जी0डी0पी0 है वह 50 हजार से भी नीचे है । यह तो दुर्भाग्य की बात है महोदय । बस एक मिनट समय लेंगे महोदय...

उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, एक मिनट । अभी जो बजट है 3 लाख 47 हजार करोड़ का बजट सरकार कह रही है । सरकार ने कहा कि हमें केंद्र से सहायता मिलेगी 52 हजार करोड़, पिछली बार भी सरकार ने कहा था लेकिन मिल कितना रहा है । 2022–23 में सरकार को 50 प्रतिशत कम मिला, 2023–24 में 58 प्रतिशत कम मिला...

उपाध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हो गया है । आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभ : अभी 43 प्रतिशत कम मिला । तो यह हाथी के दांत के समान है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी ।

श्री संदीप सौरभ : सरकार का समय लेकर हमलोगों को दो मिनट दीजिए तो हमलोग बजट का दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं ।

उपाध्यक्ष : आपको तीन मिनट मिला है । माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी, आप अपना पक्ष रखें ।

(व्यवधान)

आपके पास एक मिनट का समय है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, बजट पर बोलने के लिए मैं आसन को धन्यवाद देता हूं । महोदय, कृषि विभाग में बजट में 3677.73 करोड़ का बजट है लेकिन सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है लेकिन सरकार किसानों की उपज की खरीदारी करने में संवेदनशील नहीं है । किसान परेशान हैं । धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य सरकार हर साल कम कर रही है । जो लक्ष्य निर्धारित है उसमें भी खरीदारी नहीं हो पा रही है । एफ0आर0के0 की कमी से धान की खरीदारी ठप है । एफ0आर0के0 सप्लाई करनेवाली कंपनी एस0एफ0सी0 को एफ0आर0के0 मुहैया नहीं करा रही है जिस कारण खरीदारी की चेन टूट गई है । सरकार इस मसले पर अभीतक कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है । हमारे कैमूर जिला में धान की खरीदारी का जो लक्ष्य था 2 लाख 34 हजार 512 मीट्रिक टन है जबकि अभीतक खरीदारी 1 लाख 53 हजार मी0ट0 ही हुआ है । वही हाल रामगढ़ विधान सभा के नुआन, दुर्गावती ब्लॉक की स्थिति भी है । वहां भी 60 से 65 प्रतिशत मात्र की अभीतक खरीदारी हुई है । जबतक सरकार इसपर कोई ठोस कदम नहीं उठायेगी और किसानों की आय, जबतक किसानों की उपज की खरीदारी नहीं होगी तबतक किसानों की आय दुगुनी कभी नहीं हो सकती है । इसलिए सरकार को इसपर संज्ञान लेकर जरूर ठोस कदम उठाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट पर चर्चा हो रही है उसमें मेरे लिए समय बहुत कम है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बजट में आपने बिहार के विकास की बहुत लंबी चर्चा की है । लेकिन बिहार का विकास का आईना क्या होगा, जबतक प्रति व्यक्ति के जीवन के स्तर में कोई सुधार नहीं होगा तबतक सही मायने में बिहार का विकास नहीं होगा और इस नजरिए से जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, पलायन जो हो रहा था, रोजी रोटी की कमाई के लिए, पेट चलाने के लिए वह रुका नहीं बल्कि तेजी से बढ़ रहा है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण करवाया था जातिगत गणना के

बाद और वह बिहार का आईना दिखा रहा था उसके आधार पर बराबरी के लिए इस बजट में प्रोवीजन होना चाहिए जिसकी कमी दिखाई पड़ रही है । तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज जो जिसके बारे में चर्चा बहुत जोर से कर रहे हैं जी राम जी, मनरेगा, महात्मा गांधी से बहुत द्वेष था, नाम को हटाकर के जी राम जी किया ठीक है जितना करना है कर लो लेकिन देश की आजादी बिना महात्मा गांधी के नहीं हो सकता था । मनरेगा में जो है मजदूरों के लिए बिहार में अगर मैं आपको डाटा के साथ मैं कह रहा हूं कि बिहार में आज मनरेगा की मजदूरी 255 रुपया है, छत्तीसगढ़ में 261 रुपया है, गोवा में 378 रुपया है, गुजरात में 288 रुपया है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अजय बाबू, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अजय कुमार : बस 30 सेकंड, केरल में 369 रुपया है । क्या यह सच्चाई नहीं है कि आप जो बिहार के अंदर 255 रुपया में मनरेगा से या जी राम जी से काम करवाना चाहते हैं कोई मजदूर क्या मिलता है ? इतने बैठे हुए सदन में, एक कोई साथी हमारे बोलें कि हमारे यहां खेत में काम करने के लिए मजदूरों को 255 रुपया नहीं मिलता है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी ।

श्री अजय कुमार : मैं कंक्लूड कर रहा हूं । इसीलिए मेरा आग्रह है कि मनरेगा के मजदूरों पर केरल की तरह कम से कम 369 रुपया करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अजय जी ने जो कहा है हमारे पड़ोसी विधायक भी हैं लेकिन आप आधी–अधूरी बात क्यों कहते हैं आपने कहा कि राज्य सरकार ने जो जाति आधारित गणना कराई और उसमें जो पहली बात तो आपने कह दिया कि कमियां पाई गईं, वह कमियां नहीं सच्चाई के आंकड़े हैं और सरकार ने कुछ भी छिपाया नहीं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनायें । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उसमें 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए । आपने कहा कि उसका कुछ इसमें निदान नहीं किया गया और निदान तो ऐसा किया गया है कि उन सारे 94 लाख परिवारों के लिए विशेष योजना बनाकर उनको उसका लाभ पहुंचाने की योजना बना दी गई है जिसका इस बजट में भी जिक्र है और उन सभी चीजों पर सरकार पूरी गंभीरता से गौर कर रही है हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपने आधी बात कही, आधी छोड़ दी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी । अब आप अपना भाषण प्रारंभ करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायं । आपको वक्त मिलेगा तो बोलियेगा ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, जब हम बुतरू थे तो मेरे बाबूजी कहते थे कि चंदा मामा देखो चॉकलेट लायेंगे । आजतक वह चॉकलेट नहीं आया वैसा ही कुछ इस बजट में भी दिखाई पड़ रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महिला रोजगार योजना है मैं बता दूं मैं इस योजना का सपोर्ट करता हूं अगर यह योजना सही तरीके से सफल हो गया तो 50 प्रतिशत पलायन निश्चित तौर पर खत्म हो जायेगा यह मैं मानता हूं इस बात को । लेकिन इसमें 1 करोड़ 56 लाख लोगों को जो 2 लाख रुपया देने की बात आपने कही है इसमें तीन लाख 12 हजार करोड़ का प्रोवीजन कहां है इस बजट में अगर आप पांच साल में भी बांटते हैं तो 60 लाख तो होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं पड़ रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर गए थे उन्होंने कहा कि हरेक जिला में 14 हजार, पूरे बिहार में 14 हजार हे0 लैंडबैंक क्रिएट करेंगे, डेवलपमेंट के लिए । उसका फंड का बजट इसमें कहा है महोदय, प्रोवीजन नहीं है जो एक्जीस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसमें सब्सिडी देना बाकी है, उसका बजट में प्रोवीजन कहां है । और अगर आप इसको और देखें कि योजना मद में आपने 1 लाख 22 हजार...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : करोड़ का प्रोवीजन है । उसमें 35 प्रतिशत टोटल बजट का है इसमें तो सैलरी 80 प्रतिशत है...

उपाध्यक्ष : आप कृपया आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आप आसन ग्रहण करें ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : और यह प्रगति यात्रा में 50 हजार करोड़ और 25 हजार करोड़ आर0डब्लू0डी0 में सैंक्शन किया उसका प्रोवीजन कहां है ?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री शुभानंद मुकेश जी ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री शुभानंद मुकेश जी ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, आज इस गौरवशाली सदन में वित्तीय वर्ष–2026–27 के वार्षिक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस अभिभाषण, आपके समक्ष जो अपनी बात रखता रहा हूं उसके लिए आपका और अपने सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देवमयी जनता कहलगांव का आभार व्यक्त करता हूं ।

(क्रमशः)

टर्न–17 / मुकुल / 06.02.2026

क्रमशः

श्री शुभानंद मुकेश : यह बजट जो हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है 3 लाख 47 हजार करोड़ का ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, यह अग्रणी बनाने के रास्ते में अग्रसर है और बहुत सारी बातें जो इसमें कही गयी हैं वह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है । आज किसान की बात कही गयी, हमारे पहले वक्ता ने बहुत डिटेल में सारी

चीजों को बताया है । आज किसान को समृद्ध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है और उसके तहत जो हमलोग 3 हजार रुपये किसानों को दे रहे हैं यह उनको समृद्ध करने का कहीं–न–कहीं रास्ता सुदृढ़ करता है, आज जो हमलोग 112 की बात कर रहे थे, पुलिस की जो व्यवस्था की बात कर रहे थे, आज उस अनुदान में कहीं न कहीं 5.2 प्रतिशत आवंटित किया गया है जो हमलोगों को सशक्त और न्याय के साथ विकास की बात को दोहराता है और शिक्षा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये गौतम बुद्ध की धरती रही है और जहां शिक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए जो सर्वाधिक 21 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है 21.7 प्रतिशत का, वह न सिर्फ समृद्ध बिहार बल्कि हुनरमंद बिहार और बिहार के जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ते हैं उनको ब्रांड एम्बेस्डर बनाने में कारगर होगा, ऐसा मेरा मानना है । अध्यक्ष महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि देकर के जो किसानों के प्रति चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जतायी है और इस बजट में प्रावधान किया गया है ये पूरे भारत में इस तरह की पहली योजना होगी जहां पर इस तरह की राशि दी जा रही है । आज जीविका के माध्यम से 10 हजार रुपये दिये गये और हमारे साथी कह रहे थे कि उसका प्रावधान नहीं है । जो हम करते हैं, लिखते हैं सारी चीजों का प्रावधान करके और ये 2 लाख जो अतिरिक्त उनके व्यवसाय के लिए जो दिया जायेगा उसका भी सारा प्रावधान इसमें है और मुझे खुशी है कि इस तरह के प्रावधानों से न सिर्फ हमारी महिला समृद्ध होगी और बिहार भी सशक्त होगा । महोदय, बिहार को जो पांच नये एक्सप्रेस–वे और पुल–पुलियों का जो जाल बिछाने की बात कही गयी है वह भी एक बिहार को समृद्ध करने के लिए आगे लेकर जायेगा । हमारे ग्रामीण विकास के तहत भी हमलोगों ने 9.4 प्रतिशत की राशि आवंटित की है और वो भी आगे बढ़ायेगा । स्वास्थ्य के प्रति पूरे बजट का 6.3 प्रतिशत रखा गया है प्रावधान, जो स्वास्थ्य को और हमारे जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके विजन को, 5 हजार बेड वाला जो पी0एम0सी0एच0 बन रहा है या अतिरिक्त जो हमलोग यहां पर व्यवस्था कर रहे हैं पटना में, तो इस तरह की जो योजना को धरती पर उतारने का जो काम है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग देख रहे हैं और ये सिर्फ आंकड़े की कलाबाजी नहीं है, एक वित्तीय अनुशासन जो इसमें दिखाया है कि किस तरह से हमलोग अपने बकाया ऋण या राजस्व का संतुलन बरकरार रखने पर काम कर रहे हैं यह भी इसमें दर्शाता है और 3 प्रतिशत से कम इसमें राजकोषीय घाटा रखने की बात कही गयी है, वह निश्चित तौर पर हमलोगों के वित्तीय अनुशासन के प्रति अपनी कटिबद्धता है कि हमलोग वित्तीय अनुशासन में रहें न कि पूर्व की सरकारों के द्वारा जो घोटालों के चक्कर में हमलोग फंसे थे । मेगा स्कील सेंटर और 55 स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस की भी बात की गयी है जो हमारी नई पीढ़ी युवाओं को निश्चित तौर पर सशक्त बनायेंगे, उनका स्कील इम्प्रूव करेगा और स्कील एक बार जब, जिस बिहार को हमलोग ज्ञान की

धरती से जानते हैं तो यहां के भी बच्चे ए0आई0 से और स्कील सेट से अगर उनको जानकारी हो गयी तो निश्चित रोजगार उनको मिलने में कठिनाई नहीं होगी । एक करोड़ रोजगार और नौकरी की बात की गयी है उसके लिए भी रोड–मैप बना है और मैं मानता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग बिहार को और समृद्ध करेंगे, ये कहने की बात है कि :

''लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।''

माननीय मुख्यमंत्री जी के विगत 20 वर्षों में जितनी सहजता से और इस सामंजस्य से केन्द्र सरकार के सहयोग से केन्द्र सरकार का भी बहुत सहयोग है इस बजट में, हमारे कर का अनुदान जो मिलता है और ऊपर से उनके माध्यम से जो 50 हजार करोड़ का भी जो सहयोग है उनके इस सहयोग के लिए उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने भी इस बिहार को, एन0डी0ए0 की सरकार को सशक्त करने के लिए प्रयास किया है और ये जो रोड–मैप बना है यह बहुत विजन का डॉक्यूमेंट होता है और दूरगामी इसके रिजल्ट निकलते हैं । मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष के पास बेचैनी है कि 10 हजार रुपये जब बंट गये तो हस्र यह था तो 2 लाख बंटेंगे तो फिर क्या होगा तो कहीं बेंच में बैठने की जगह न रह जाए तो इस तरह की बात है तो डर है, उनको भी डर लगना चाहिए अच्छे काम से अगर हमलोग आज आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग और आगे बढ़ेंगे और जिस हिसाब से यह बजट बना है, मैं समझता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी का और हमारे नेता का जो इसमें मार्गदर्शन मिला, यह सचमुच में हमलोगों के लिए सौभाग्य है कि समृद्ध बिहार बनाने में हमलोगों का योगदान रहे और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, इस महती सभा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अखतरूल ईमान साहब । आपके पास पांच मिनट का वक्त है।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली 20 साल की पुरानी सरकार का यह बजट हमारे सामने में है जिस पर हम इजहारे–ख्याल कर रहे हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने बुजुर्ग मिनिस्टर को जो हमलोगों के गार्जियन भी हैं, शरीर से भले ही बुजुर्ग लग रहे हैं लेकिन बजट पेश करते हुए या क्वेश्चन का एन्सर देते हुए हमलोग उनको दिल से, दिमाग से और आंख से जवानों पर भारी समझ रहे हैं और मैं मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं कि इन्होंने अपने बजट के आगाज में मेरा ही नाम लिया है सर । ईमानदारी की बात उन्होंने कही है, ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बात शुरू की है लगता है कि मेरा प्रेम भी है दिल में और इन्होंने सात निश्चय, सरकार के सात निश्चय शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी

ढांचे पर भी बड़ी तवज्जो देने की बात कही है और 3 लाख 47 हजार करोड़ का एक बड़ा बजट दिखाया है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बजट का आकार जरूर बढ़ा है लेकिन बिहार की जनता पर इसका क्या व्यापक असर पड़ा है सर । अगर उस पर आप मुआवजना करें सर तो हमें यह लगता है कि–

''बड़ा शोर सुनी थी पहलू में दिल का,
जो चीरा तो कतरा भर खून तक न निकला ।''

क्या फायदा हुआ है बजट का, बजट साइज बढ़ा, यह बजट का पैसा कहां से आया, माल महराज का, मिर्जा खेले होली । जो भी आपके यहां आमदनी हुई है, जो भी रिमिटेंश आया है वह परदेशी मजदूरों से आया है, पलायन रुका नहीं और उस बेचारे गरीब का तो आज झोला कुछ भरा नहीं, गरीबों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है । 20 साल पुरानी सरकार को इस नये बजट में तो एन0आई0टी0 के नये सेंटर की बात करनी थी, मेडिकल हब बनाने की बात करनी थी, सीमांचल में कैंसर रोग से लोग बीमार पड़ रहे हैं कैंसर इन्सटिच्यूट खोलने चाहिए थे, वही पुरानी लकीर के फकीर बनकर रह गये हैं और यह कह रहे हैं हमलोग 3 लाख 47 हजार करोड़ का बजट लेकर आये हैं। दरहगिरा आंधी न पगला बोला मैंने उखाड़ दिया, इसने क्या किया भाई । सवाल यह पैदा होता है कि अगर बजट बढ़ा है तो पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ी हमारी, आज राष्ट्रीय औसत 2 लाख 53 हजार का है सर और झारखंड जैसा, उड़ीसा जैसा गरीब लोग हमसे आगे हैं सर । झारखंड में 1 लाख 16 हजार, उड़ीसा 1 लाख 61 हजार प्रति व्यक्ति आय है और हमारे यहां आज भी 69 हजार ही है और सीमांचल में तो सर 26 हजार से भी कम है, सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल में है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया और कहा जाता है कि यही बजट आगे का भविष्य तय करता है, फ्यूचर प्लान सरकार के पास नहीं है और किसी भी लोकतंत्र में, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है सर, लोकतंत्र की जननी रहने में लोकतंत्र वहीं स्थापित रहेगा सर जहां माइनोरिटी के लोग, दलित के लोग खुशी से रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया जाति आधारित जनगणना कराया और उसमें 2 लाख नौकरियों से मुस्लिम माइनोरिटी वंचित रही, इसमें मुस्लिम माइनोरिटी के लिए कुछ भी नहीं । पिछले साल से भी बजट सर 1100 करोड़ था अबकि बार 800 करोड़ कर दिया ।

क्रमशः

टर्न–18 / सुरज / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री अखतरूल ईमान : पिछले साल भी बजट सिर्फ 11 सौ करोड़ था, अब की बार 8 सौ करोड़ कर दिया गया है । मामला यह है कि माइनोरिटी के लोगों का बुरा हाल

है । सबसे कम पढ़–लिखे, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बीमार और उन पर मामला यह हो रहा है कि आज उनका उत्थान नहीं हो रहा है । मदरसे की हालत बुरी है । मदरसे का बजट नहीं बढ़ाया गया । मदरसे के बच्चों को स्कूल के बच्चों के बराबर पोशाक नहीं दी जा रही है । टीचरों की तनख्वाह नहीं बढ़ायी गयी है । अंतर वेतन की राशि 02 हजार करोड़ का मामला था, साढ़े चार सौ करोड़ दिया है । टीचर मर रहे हैं और अंतरवेतन की राशि उनको नहीं मिल पा रही है । माइनोरिटी खौफ में है । आज ऑफिसर्स की बहाली में एस0पी0 हो, डी0एम0 हो, एस0डी0ओ0 हो, थाना प्रभारी हो कहीं भी माइनोरिटी के लोग बहाल नहीं किये जा रहे हैं । माइनोरिटी के लोगों का बुरा हाल हो रहा है । आतहर का नवादा से, शहजाद का बेगूसराय में मॉब लिंचिंग हो गया । नुरशेद आलम को सुपौल में मार दिया गया । हिना खातुन, मधेपुरा जो 06 बच्चों की मां है, उसके साथ रेप हुआ । झंझारपुर में कयुम, पिता–मोहम्मद डोमू को मारा गया । शहजाद को बेगूसराय में मारा गया । मोहम्मद फैजान एक बच्चा है पश्चिमी चंपारण का, जो लापता है 26.04.2025 से, अफरोज जमुई का 17.12.2025 से लापता है । इधर लॉ एंड आर्डर का मसला यह है कि नीट की छात्रा के साथ रेप होता है, उसका मर्डर होता है । बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कहां से होगा ? मामला यह है कि आज हमारे सीमांचल में सूरज बिहारी नाम का एक युवक जो मक्के का व्यापारी था मारा गया और उसके गम में आज उसके बाप को हर्टअटैक आ गया । क्या दे रहे हैं शांति हम दे रहे हैं ? सीमांचल हमारा सबसे गरीब है । आप कह रहे हैं, बराबरी का नारा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री पर हम विश्वास करते हैं कि अगर बराबरी का कुछ नहीं कर पाये हैं मुख्यमंत्री जी तो इस पांच साल में कम से कम हमारा इंसाफ कर दीजिये । सबसे ज्यादा बाढ़ हमारे यहां है, सबसे ज्यादा सुखाड़ हमारे यहां है, पलायन हमारे यहां है, गरीबी हमारे यहां है और कैंसर की बीमारी हमारे यहां है । आर्सेनिक है पानी में, यूरीन है पानी में । कैंसर की बीमारी 30 प्रतिशत आ रहा है । यह जो रिपोर्ट आयी है महावीर कैंसर संस्थान की कि 10 फीसद आबादी सीमांचल की आज 30 फीसद कैंसर की बीमारी, आर्सेनिक है वहां पर । मैं साधुवाद देना चाहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर को कि कम से कम पूरे सरकार के दरम्यान में रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो जमीन का जंजाल है, इसको खत्म करने का प्रयास किया है । लेकिन आज हमारे यहां मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि निजी जमीन पर काम करने वाले, मिट्टी काटने वाले को कोई सरकारी परमिशन नहीं लेना पड़ेगा । आज हमारे यहां हजारों ट्रैक्टर चालक धरने पर बैठे हुये हैं किशनगंज और पूर्णिया में । अपने निजी काम के लिये मिट्टी...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक सेकंड...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय हो गया है ।

श्री अखतरूल ईमान : उसकी गाड़ी सीज की जाती है, एक लाख रुपया उस पर जुर्माना किया जा रहा है तो मिट्टी कहां से मिलेगी । मजदूर किसान जो मिट्टी लेता है उसकी मिट्टी को ये लोग पकड़कर ले जाते हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, दो–तीन बातें हैं । हाईकोर्ट का बेंच, ए0एम0यू0 और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के ताल्लुक से...

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये प्रस्तुत बिहार बजट के समर्थन में अपना विचार व्यक्त करने के लिये इस सदन में खड़ा हुआ हूं । इसके लिये सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया । मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बहुत–बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बिहार बजट पर बोलने का अवसर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर के देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं जिसकी वजह से मैं आज यहां बोल रहा हूं । हमारे माननीय वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी ने 03 फरवरी, 2026 को यह बजट प्रस्तुत किया जिसका आकार 03 लाख 47 हजार 589.76 करोड़ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिहार के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा बजट है और साथ ही पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 30 हजार 694 करोड़ अधिक है । जबकि 2005 में जो बजट पेश हुआ था वह 23 हजार करोड़ रुपये का था ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट सात निश्चय–3 की परिकल्पना और रोड मैप के तहत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास, रोजगार श्रृजन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना एवं आम जन के कल्याण को गति देता है । यह बजट वंचित, शोषित, दलितों का बजट है । इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 68 हजार 216 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है जिससे शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या तथा गुणवत्ता में सुधार संभव होगा । इस बजट में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर पर्याप्त आवंटन किया गया है ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार तथा ग्रामीण रोजगार अवसर सुनिश्चित किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिये विशेष योजनाएं और स्वराज्य कार्यक्रमों का समर्थन किया गया है । इसके अतिरिक्त इस बजट में औद्योगीकरण, ऊर्जा, सुरक्षा और पुलिस विभाग के विस्तार पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिसमें से कई विभाग के बजट में वृद्धि की गयी है, जिससे नए रोजगार, सुरक्षा बढ़ोतरी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ सामूहिक विकास की सोच पर आधारित है, जिसमें पूंजीगत व्यय पर जोर देकर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार, सड़क, जल, बिजली तथा स्मार्ट शहरों की उन्नति के लिये संसाधन आवंटित किये गये हैं । इस बजट में विपक्ष के लोग कहते थे कि विकास नहीं हुआ है । मैं 1990 के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं कि एक शहर से दूसरे शहर । जब हमलोग सहरसा से सुपौल जाते थे तो करीब हमलोगों को तीन घंटा का समय लगता था और आज सहरसा से सुपौल जाने में आधे घंटे का समय लगता है क्या यह विकास नहीं है और ये लोग केवल हल्ला करते रहते हैं कि विकास नहीं हुआ है । इस बजट में सड़कों...

(व्यवधान)

एक बार घुमिये, देखिये सड़क । हमलोग कहीं भी बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे से तीन घंटे में पटना पहुंच जाते हैं । सहरसा से पटना की दूरी जो कि ढाई सौ किलोमीटर है तीन घंटा में हम पहुंच जाते हैं और ये सब तीन घंटा में । खगड़िया और मानसी होकर के बेगूसराय होकर के तीन घंटे में हमलोग पटना पहुंच जाते हैं । इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर नागरिक के लिये न्यायोचित अवसर और विकास सुनिश्चित किया है । मुझे विश्वास है कि यह बजट बिहार को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक जनशक्ति पाटी (रामविलास) के संस्थापक पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जीवन भर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिये संघर्ष किया । यह बजट उसी विचारधारा की झलक है जहां विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), एन0डी0ए0 के इस गठबंधन में सामाजिक न्याय, युवाओं की आकांक्षा और समावेशी विकास को मजबूत आवाज बनेगी । हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इस बजट से पूरी तरह मेल खाता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, सिमरी बख्तियारपुर से जीतकर आया हूं । यह क्षेत्र कोशी और बाढ़ से पीड़ित है । यहां पर कोशी नदी के तटवर्ती इलाकों में सड़क, जलजमाव एवं कटाव की जटिल समस्या है और इन समस्याओं से सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा के लगभग 15 पंचायत प्रभावित हैं । इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन धार्मिक स्थल भी हैं । बाबा मटेश्वर धाम, बाबा खीरहरिस्थान और मां तारा स्थान । पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है । बाबा मटेश्वर धाम को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने पर सरकार को इससे अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होगी । इस प्रकार यह बजट

बिहार में सम्पूर्ण विकास में मील का पत्थर साबित होगा और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती दीपा कुमारी ।

टर्न–19 / धिरेन्द्र / 06.02.2026

श्रीमती दीपा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपका बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अपनी पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी का भी आभार जताना चाहती हूँ जिन्होंने हम जैसी महिलाओं को साहस और एक प्लेटफार्म दिया, जहाँ से बिहार की महिलाएं इस सदन में भागीदार बन रही हैं और साथ में इमामगंज की देवतुल्य जनता को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने यहाँ भेजने में अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के बिहार बजट पर अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा की बात पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहती हूँ । सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी तथा माननीय वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी को 03 लाख 47 हजार करोड़ से अधिक के इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देती हूँ । यह सिर्फ बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट नहीं है बल्कि यह उन लोगों के लिए जवाब है जो सालों से कहते रहे कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पिछले वर्ष से करीब 30 हजार करोड़ रुपये अधिक है । इसका साफ संदेश है, यह सरकार बहाने नहीं बनाती है बल्कि काम करती है, काम करके दिखाती है । जो लोग हर बजट को कागजी करार देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सड़कें कागज पर बनी हैं ? क्या स्कूल, अस्पताल और बिजली सिर्फ भाषणों में नहीं हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं । सच्चाई यह है कि बिहार आज बदल रहा है और यह बदलाव आँकड़ों में भी दिखाई देता है, जमीन पर भी दिखाई देता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 63 हजार करोड़ रुपये बुनियादी ढाँचे पर खर्च किए जा रहे हैं, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और बिजली पर । यह वही काम है जिनकी कमी का रोना दशकों तक रोया गया है और आज जब काम हो रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए 68 हजार करोड़ का प्रावधान है । यह उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जिन्होंने बिहार को अंधेरे में रखने की राजनीति की

। आज बिहार का बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और अपने हक की बात कर रहा है । स्वास्थ्य के लिए 21 हजार करोड़ रखे गए हैं ताकि गरीब आदमी इलाज के लिए मजबूर होकर दूसरे प्रदेशों की ठोकर न खाए, यह फर्क है दिखावे की राजनीति और जनसेवा की राजनीति में ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के लिए 23 हजार 701 करोड़, ऊर्जा के लिए 18 हजार 737 करोड़, सड़कों के लिए 17 हजार 716 करोड़ और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 02 हजार 86 करोड़, अल्पसंख्यक, पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए करीब 02 हजार करोड़ । ये आँकड़े चीख–चीखकर बताते हैं कि यह सरकार सिर्फ बात नहीं करती है, न्याय भी करती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान, मजदूर और गाँव इस सरकार की प्राथमिकता है । इमामगंज जैसे पहाड़ी और पिछड़े इलाकों को इस बजट से सीधा फायदा मिलेगा । जो लोग कभी इन इलाकों का रास्ता तक नहीं जानते थे, आज वही लोग विकास पर सवाल उठा रहे हैं, यह सबसे बड़ा मजाक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं महिलाओं की बात करना चाहती हूँ क्योंकि यहीं से बिहार की असली ताकत निकलती है । करीब 01 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10–10 हजार रुपये देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया, अब व्यापार बढ़ाने के लिए 02–02 लाख रुपये अतिरिक्त राशि दिये जायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कल बजट पर हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वे बोल रहे थे कि बिहार में कोई ऐसा काम है जो आप बता दें कि एक नंबर पर है तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पक्ष की भी महिलाएं हैं और आपके विपक्ष की भी महिलाएं हैं तो इन महिलाओं से, खासकर विपक्ष की महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, हम बहुत सारी भूमिकाओं के साथ घिरे रहते हैं और बखूबी उन भूमिकाओं को निभाते हैं तो हम उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि हम घर संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, पति की देखभाल करते हुए, हम अपने बूढ़े माता–पिता का ख्याल रखते हुए घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकल कर काम करते हैं और यहां तक कि हम अपने सदन में आकर पुरुषों के साथ कदम–से–कदम मिलाकर चल रहे हैं और अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं । यह तो हम समझते हैं कि हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी की देन है कि आज महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी चीजों में महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है । 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में, 50 प्रतिशत शिक्षक बहाली में, 35 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में, पी॰जी॰ तक मुफ्त पढ़ाई, साईकिल, पोशाक, जीविका और उद्यमिता । उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषणा नहीं, क्रांति है । अगर महिला सशक्तिकरण पर दुनिया में कोई असली पुरस्कार होता तो माननीय मुख्यमंत्री श्री

नीतीश कुमार जी उसके सबसे मजबूत दावेदार होते और पहला नंबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का होता । यह बिहार की बेटियों की आवाज है, कोई नारा नहीं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यवाओं के लिए रोजगार और हुनर की योजनाएं इस बात की सबूत है कि यह सरकार सिर्फ आज नहीं, आने वाले बिहार की तैयारी कर रही है । किसानों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरूआत कर हरेक किसान को राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रतिवर्ष 03 हजार की मदद करेगी । लघु जल संसाधन विभाग 01 लाख निजी नलकूप लगवाने का काम करेगा, वहीं अब आगे बिहार उद्योग भी खड़ा करेगा, जिसका संकल्प बजट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और सबसे अहम बात राजकोषीय घाटा 03 प्रतिशत के भीतर है । मतलब विकास भी हो रहा है और राज्य कर्ज में भी नहीं डूब रहा है । यह है जिम्मेदार शासन ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग हर बात पर नकारात्मकता फैलाते हैं, उन्हें यह बजट जवाब है । जो लोग बिहार को पिछड़ा कहकर राजनीति करते हैं, यह बजट उन्हें आईना दिखाता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती दीपा कुमारी : महोदय, अगर इस बजट को ईमानदारी से...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका समय हो गया है ।

श्रीमती दीपा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं जब वर्ष 2005 से पहले फतेहपुर की पहली महिला होउंगी जहाँ मैं साईकिल चलाती थी और जब साईकिल चलाकर बाहर रोड पर निकलती थी तो उस समय लोग हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, मजाक उड़ाते थे कि देखिये लड़की साईकिल चला रही है । लड़के आवाज लगाते थे कि लड़कियां देखो साईकिल चला रही है तो महोदय, कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2005 से पहले की सरकार जो थी कि लड़कियों को देखकर लोग मजाक उड़ाते थे और हल्ला करते थे और आज की जो सरकार है तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तरह–तरह की काम कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए महिलाएं अपना काम कर रही हैं । हम खासकर उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी, आपके नेता प्रतिपक्ष महिला के ऊपर सवाल उठाते हैं, महिला के ऊपर टिप्णियां करते हैं तो आप भी महिला हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती दीपा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, ये भी महिलाएं हैं, उनसे भी खासकर हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने नेता प्रतिपक्ष को बोलिये कि महिला के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, महिला आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में महिलाएं अव्वल रहेंगी, पुरुष से आगे बढ़ कर काम करेंगी । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रूहेल रंजन जी ।

श्री रूहेल रंजन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया और मैं हमारे अभिभावक सी॰एम॰ माननीय श्री नीतीश कुमार जी को इस सदन में आने का मौका देने के लिए मैं अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस गरिमामय सदन में वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत बिहार बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ । यह बजट केवल आँकड़ों का दस्तावेज नहीं है यह बिहार के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का घोषणा–पत्र है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का बिहार वह बिहार नहीं है जिसे कभी पिछड़ेपन का पर्याय माना जाता था आज का बिहार विकास, निवेश, रोजगार और सामाजिक न्याय की नई पहचान गढ़ रहा है...

....क्रमशः....

टर्न–20 / अंजली / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री रूहेल रंजन : और यह बजट उसी परिवर्तनशील बिहार की तस्वीर प्रस्तुत करता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है वित्तीय अनुशासन के साथ विकास । सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास कर्ज के बोझ से नहीं, बल्कि राजस्व प्रबंधन और प्राथमिकताओं की स्पष्टता से होगा । यह बजट बताता है कि बिहार अब केवल खर्च करने वाला राज्य नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश करने वाला राज्य बन चुका ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए बढ़ा हुआ बजटीय प्रावधान यह संकेत देता है कि सरकार भविष्य की पीढ़ी को केंद्र में रखकर नीति बना रही है । विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे का सुधार किया जा रहा है । डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है । उच्च शिक्षा संस्थानों और कॉलेजों का विस्तार का किया जा रहा है । यह बजट मानता है कि शिक्षा पर खर्च, व्यय नहीं, निवेश है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ा हुआ आवंटन यह दर्शाता है कि सरकार के लिए गरीब का जीवन सबसे कीमती है । जिला अस्पतालों का सशक्तिकरण हुआ है मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की गई है । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया है ।

यह बजट बीमारी के इलाज के साथ–साथ बीमारी के रोकथाम और स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा पर भी जोर देता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की आत्मा गाँव में बसती है और यह बजट गाँव को मजबूती देता है । सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जा रहा

है । कृषि यंत्रीकरण किया जा रहा है । ग्रामीण सड़कों और बाजार को संपर्क से सुधारा जा रहा है । यह बजट किसानों को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार मानता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन की ओर देखिए ।

श्री रूहेल रंजन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट युवाओं की आकांक्षाओं को भी समझता है । सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम लागू किया है । स्टार्ट–अप और रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है । सरकार यह संदेश दे रही है कि बिहार का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यह सिद्ध करते हैं कि यह बजट समावेशी विकास का बजट है । यह बजट कहता है, विकास वही है जिसमें आखिरी व्यक्ति भी साथ चले ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क, पुल, बिजली और शहरी ग्रामीण संपर्क–ये सभी इस बजट की प्राथमिकताओं में हैं । बुनियादी ढाँचा केवल निर्माण नहीं करता, यह अवसर, निवेश और विश्वास का निर्माण करता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट आशा का बजट है, विश्वास का बजट है और बिहार को अगले दशक के लिए तैयार करने वाला बजट है । मैं इस दूरदर्शी संतुलित और जनहितैषी बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को इस्लामपुर विधान सभा के भाई–बहनों की तरफ से बधाई देता हूं और इस बजट का पूरे विश्वास से समर्थन करता हूं । धन्यवाद । जय बिहार, जय नीतीश कुमार ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री माधव आनंद जी ।

श्री माधव आनंद : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोइंसिडेंस है कि 1 तारीख को भारत सरकार ने बजट पेश किया और 3 तारीख को बिहार सरकार ने भी बजट पेश किया और जब दोनों बजट को हमलोग एनालिसिस करते हैं तो बहुत कुछ समानताएं नजर आती हैं दोनों बजट में चूंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में...

(व्यवधान)

शांत हो जाइए । समानताएं बहुत कुछ देखने को मिल रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है सबसे पहले तो मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ, वित्त मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा बजट पेश किया । इस बजट में बहुत सारी चीजें हैं उपाध्यक्ष जी जिस पर अगर चर्चा करने लगें तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, आंकड़ा देने की आवश्यकता पड़ जाएगी, चूंकि टाइम कम है, क्योंकि मुझे 4 मिनट का ही वक्त दिया गया है तो संक्षेप में ही अपनी बात को रखना चाहूंगा । उपाध्यक्ष जी, इस बजट में जो अभी वर्तमान आवश्यकताएं हैं उसको तो ध्यान में रखा ही गया है, साथ ही साथ जो भविष्य की अपनी बिहार की अर्थव्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखा गया है और वित्तीय अनुशासन का भी अनुपालन किया गया है । जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, फिसिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब वित्तीय अनुशासन किसी अर्थव्यवस्था में दिखता है, तो जो निवेशक हैं वे आकर्षित होते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2005 से जिस तरह से लगातार बजट का आंकड़ा बढ़ा है और जब हमलोग पहले पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि एल0पी0जी0 प्रोसेस कहते थे, Liberalization, Privatization, and Globalization की बात हमलोग करते थे । जब वर्ष 2005 में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि उस टाइम से एल0पी0जी0 प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आज का बजट जो है, उस रूप में देखा जाय, तो जो बाहर के निवेशक हैं, सिर्फ मैं यह नहीं कहता हूं कि जो भारतवर्ष के निवेशक हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी बिहार में आने का काम करेंगे यह मुझे पूरा विश्वास है इस बजट के माध्यम से ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमलोग पलायन की बात करते हैं, बहुत सारे साथियों ने पलायन की बात कही है, हमलोगों ने 2005 से पहले की भी स्थिति देखी है और कहीं न कहीं उस टाइम में हम भी छात्र जीवन में थे और पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, अगर पटना से, बिहार से दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ी, तो कहीं न कहीं उस समय की अर्थव्यवस्था, कहीं न कहीं उस समय रोजगार सृजन पर काम नहीं होना, कहीं न कहीं उस समय की व्यवस्थाएं हमलोगों को मजबूर कर दिया है...

(व्यवधान)

शांत रहिए । लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांत रहिए । टोका–टोकी नहीं कीजिए । माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय । टोका–टोकी नहीं, आपको भी वक्त मिलेगा ।

श्री माधव आनंद : उपाध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं, शांति बनाएं ।

श्री माधव आनंद : कि आज दिल्ली से पुनः इस सदन का हिस्सा बना हूं तो कहीं न कहीं पलायन रोकने में जो सरकार काम कर रही है उनका योगदान है और आज मैं इस बिहार विधान सभा का सदस्य बना हूं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण । जब हमलोग बात करते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था का, हमलोगों ने देखा है कितना काम हुआ है और संस्कृत में हमलोग कहते हैं –''प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम्'' संस्कृत में श्लोक है प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम् और बाजार में जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमलोग कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, दोनों का अगर सारांश निकाला जाय तो यहां काम दिखता है और जब दिखता है तो स्वाभाविक है कि जब हमलोग चुनाव लड़े हैं, तो जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए गए थे उस समय एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था मोदी और नीतीश की जोड़ी के बारे में, तो वही हमलोगों का है जो दिखता है वही बिकता है । जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसी के कारण है कि आज हमलोग इतनी बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से भी नाता रखता हूं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं, कृपया शांति बनाए रखिए ।

श्री माधव आनंद : आज हम मधुबनी विधान सभा क्षेत्र को रिप्रजेंट कर रहे हैं । जब मैं यहां से दिल्ली जाता हूं, जब प्राइवेट निवेशकों से मिलता हूं, जब माननीय मंत्री जी से मैं मिलता हूं तो अब वहां जो प्राइवेट निवेशक बैठे हुए हैं, बड़े–बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके मन में यह रहता है कि अब क्यों न हम बिहार की तरफ देखने का काम करें । मैंने कई बार, पिछले सत्र के बाद भी मैं दिल्ली गया ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं ।

श्री माधव आनंद : शांत हो जाइए, आपकी बारी आएगी, शांत हो जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं ।

श्री माधव आनंद : तो वहां निवेशक आने के लिए तैयार हैं और मैं यह कहता हूं अगर इन लोगों को विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है, आज पटना का जो एयरपोर्ट है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहां मरीन ड्राइव बनाया है, इसी मरीन ड्राइव का

आनंद प्रतिपक्ष के नेता भी उठाने के लिए गए थे । प्रतिपक्ष के नेता पूरी फैमिली के साथ उठाने के लिए गए थे, वहां डांस कर रहे थे...

(व्यवधान)

अच्छी बात है ।

उपाध्यक्ष : शांति बनाइए ।

श्री माधव आनंद : आप भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, चश्मा थोड़ा बदल लीजिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं माननीय सदस्या ।

श्री माधव आनंद : विकास के साथ आइएगा तो जनता आपको आशीर्वाद देगी और सिर्फ बे–बुनियाद बातें करेंगे तो जनता आशीर्वाद नहीं देगी । यही कारण है, नकारात्मक राजनीतिक आपलोग कर रहे हैं, तो आज संख्या बल आपलोगों की कितनी कम हो गई ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शोरगुल नहीं ।

श्री माधव आनंद : हो सकता है इसी तरह नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे तो हो सकता है कहीं जीरो पर ही अगली बार न आ जाएं । इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट है, सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद आज बिहार जिस रूप में विकास कर रहा है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठे–बैठे मत बोलें । शांति बनाएं ।

श्री माधव आनंद : और यह जो 5 साल का कार्यकाल होगा, वह विकास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और जो हमलोगों ने लक्ष्य रखा है एक करोड़, रोजगार सृजन पर एक बात करी हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या शांति बनाएं ।

श्री माधव आनंद : एक करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन पर जब प्राइवेट निवेशक आने लगेंगे, तो एक करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन यहां होगा । जिस तरह कैबिनेट के पहली मीटिंग में ...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया शांति बनाएं ।

श्री माधव आनंद : जितनी चीनी मिले बंद पड़ी हुई हैं सबको पुनर्जीवित करने की बात कही गई । मैं तो कहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी...

(व्यवधान)

हमलोग तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमलोग के पास दो ब्रांड एंबेसडर है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय

नरेंद्र मोदी जी, दो ब्रांड एंबेसडर हमलोग के ऐसे हैं और जब दो ब्रांड एंबेसडर ऐसे हों जो सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हैं तो हमलोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / पुलकित / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री माधव आनंद : उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, किसी भी सरकार के लिए तीन चीज बहुत आवश्यक है नीति, नियति और ईमानदारी ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री माधव आनंद : ये तीन चीजें मेरे दोनों ब्रांड एंबेसडर में कूट–कूट के भरी हुई है । कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी करप्शन में है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति आज से नहीं, नीतीश कुमार जी 2005 से रखते हैं और वही नीति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं । महोदय, स्वाभाविक है कि जब हम लोगों की नीति, नियति और ईमानदारी हो, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है विकसित भारत और विकसित बिहार, वह निश्चित रूप से हो कर रहेगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या शांति बनाये रखें ।

श्री माधव आनंद : मैं आपके माध्यम से, आसन के माध्यम से सरकार को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जैसे युवा साथी की जहां आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे । बहुत–बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद । आप अपना पक्ष रखें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 पर आपने हमको बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, कई हमारे साथियों ने, चाहे रजनीश जी हों, बैद्यनाथ जी हों, हमारे कई साथियों ने डाटा बहुत दिया है, हम उस डाटा के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, दोहराना नहीं चाहते हैं । हम सीधे–सीधे तौर पर बात करना चाहते हैं। हम कहां से चले हैं ? हम यदि पीछे मुड़कर देखते हैं, आप जब 2004 और 2005 के बजट का मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं, तो उस समय 3000 करोड़ का मात्र बजट था । उसमें उनकी प्राथमिकता में क्या था ? चरवाहा विद्यालय। 113 चरवाहा विद्यालय के लिए उन्होंने 01 करोड़ का प्रावधान किया था । महोदय, यह उस समय का आलम था कि ये लोग जो गैर योजना थी, गैर योजना का भी बजट उसको पूरा नहीं कर पाते थे, योजना के बजट की तो कल्पना ही करना बेकार है । वहां से

हम चले हैं 2005 से 2006 तक, जो माननीय स्वर्गीय हमारे सुशील कुमार मोदी जी से जो कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रारंभ हुआ, आज आदरणीय बिजेन्द्र यादव जी के पास तक आया है । इस क्रम में हमने विकास की कई ऊंचाई को छूने का काम किया है । जहां 23 हजार करोड़ से शुरू हुआ, आज हम लोग 3,47,589. 76 हजार करोड़ तक हम लोग पहुंच गए हैं । महोदय, इसमें हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं ? हमारी प्राथमिकताएं शिक्षा है । चूंकि किसी भी राज्य हो या देश हो, इसका विकास मानव विकास पर निर्भर करता है और हमारी सरकार ने उसको प्राथमिकता में रखा है । यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को खाने से लेकर, पोशाक से लेकर, लिखने–पढ़ने तक, किताब तक मुफ्त मुहैया करायी है । उच्च शिक्षा के लिए उसको अलग से रिजल्ट के प्राप्तांक के आधार पर अलग से प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है । कमीशन में बैठने वाले छात्रों के लिए भी मेन्स की तैयारी करने के लिए, फाइनल की तैयारी करने के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि का उपयोग किया गया है, प्रावधान किया गया है । यही कारण है कि आज बिहार के छात्र केंद्रीय जो नौकरियां हैं, प्रदेश से लेकर केंद्रीय नौकरियों में एक अलग परचम फहराने में कामयाब हो रहे हैं । महोदय, यह आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है और निश्चित रूप से यह जो प्रावधान इस बार किया गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का जो विकसित भारत और बिहार को राज्य के अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, इस संकल्प को आने वाले दिनों में पूरा करेगा महोदय, यह बजट उसका प्रतिबिंब है ।

हमारे साथी कई लोग कह रहे थे, इनको विकास दिखता नहीं है। हमारे गांव में एक कहावत है कि जेठ का जो अंधा होता है, उसको सावन में भी सूखा–सूखा ही नजर आता है । महोदय, जिसका इलाज बिहार में छोड़िए शंकर नेत्रालय जैसे अस्पताल में भी उसका इलाज नहीं है, चूंकि वे लोग जेठ में अंधे हुए हैं, उनको सावन का हरा–भरा दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं देगा। हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि जब इन्हीं के नेता गंगा पथ पर जाते हैं, तो रोड की जो खूबसूरती को देखकर उनका स्वतः स्फूर्त कमर हिलने लगता है, डांस करना शुरू कर देते हैं । यह बात अखबार ही बोल रहे हैं । ये लोग हमारे साथी बार–बार कहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार है, अब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है ? साथियों, आपको बताना चाहता हूं, अखबार वाले ही कई बार लिखे हैं कि हमारे नेता थैला लेकर गए, उधर बोरा से भरकर आए । यह केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं कि हम जितनी मांग करते हैं, हमारी जो आशा रहती है, उससे ज्यादा केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है । महोदय, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार विकसित श्रेणी में खड़ा होगा । हमारे ऊपर जो कलंक का टीका लगा था कि बिहार बीमारू राज्य है, दुनिया मान चुकी थी कि

अब बिहार सुधरने वाला नहीं है, वहां से बिहार चला है । आज देश के जितने भी राज्य जिन्होंने विकास दर को प्राप्त किया है, उसमें बिहार अव्वल है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा । महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, 2047 में विकसित भारत बनाने की, उसमें बिहार का अहम योगदान होगा । साथियों, इस बात से आप आश्वस्त रहिए । इसलिए महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, जो बजट है, मैं इसका समर्थन करता हूं और अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय बिजेन्द्र यादव जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, विजय चौधरी जी, इन लोग का जो कुशल वित्तीय प्रबंधन हुआ है, इसी का आज परिणाम दिख रहा है साथियों । इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बाबुलाल शौर्य जी ।

श्री बाबुलाल शौर्य : हम अपने आसन को, माननीय उपाध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें बोलने का मौका मिला । हम अपनी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि एक सामान्य लड़के को आज संविधान के मंदिर में आने का मौका मिला, उन्होंने विश्वास जताया । उस परबत्ता की धरती को, उत्तर त्रिवेणी, उत्तर वाहिनी तट, अगवानी घाट, परबत्ता विधानसभा की उस धरती से आज हम जीत कर आए, वहां के देवतुल्य जनता को भी हम साधुवाद देते हैं ।

हम लोग जिस क्षेत्र से आए हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र को फरकिया लोग कहते थे । फरकिया, राजा टोडरमल ने जिसमें फर्क कर दिया था और आज उस फरकिया का नाम बदल कर खगड़िया कर दिया गया। खगड़िया खग का जहां बसेरा है । वहां आप जाइए, घूमिए, सब लोग जाकर घूमिए । उस तरह का रोड, पैरा, पुल, पुलिया का जाल बिछा दिया, यह है बजट का पहली प्राथमिकता । यह जो बजट है, उस बजट की प्राथमिकता अगर देखनी है तो आप लोग भी जाकर के देखिए । किस तरह से सीमांचल क्षेत्रों में जाल बिछा है । जो खगड़िया सात नदियों से घिरा हुआ खगड़िया है, सात नदियों का नैहर कहते हैं खगड़िया को और वह खगड़िया जो है, आप कहीं से कहीं चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वह धरती आज विकास के रूप में रोल मॉडल है, वह आप लोग जा के देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी के विकास को आप लोग जाकर के देख सकते हैं।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों । यह प्रसिद्ध शेर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार की नीति और नीयत बयां करती है ।

अध्यक्ष महोदय, किसने सोचा था कि वर्ष 2004 और 2005 में, 2005 का बजट मात्र 23,885 करोड़ था, वही आज वित्तीय वर्ष 2026–27 में 15 गुना बढ़कर 3,47,589 करोड़ हो चुका है । यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बस इसलिए संभव हो सका, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने तबीयत से विकास का पत्थर उछाला है, जिससे बिहार और बिहारवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सका है ।

अध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि दिखता क्या है ? हम लोग 2005 से पहले के बिहार की तुलना क्योंकि लोग तुलना पर औना जाते हैं, बौखला जाते हैं कि तुलना क्यों करते हो भाई । तुलना तो जिसका शासन था 15 साल का शासन और उसके बाद उसी की तुलना सड़क गड्ढे में थी कि गड्ढा सड़क में था, यह देखने की जरूरत है । आज आप सब लोग भी गाड़ी से आते होंगे । सीवान से भाई आपके आते होंगे और दो घंटे में आप सीवान से सदन आते हैं और सदन से सीवान चले जाते हैं भाई, ये नीतीश कुमार का विकास है । ये नीतीश कुमार का विकास है । आप देखते हैं, जाइए स्कूल में। हम लोग तो नदी किनारे से, सात नदियों से घिरी हुई जगह से आए हैं न। वहां के स्कूल में बच्चे बकरी चराते हुए नजर आते थे । आज देखिएगा, पढ़ाई करके बकरी चराने का काम करते हैं, ये स्कूल का विकास हुआ है, जाकर के देखिए । हर जगह देखिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए । हमलोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में...

(व्यवधान)

चराना, काम करना कोई छोटा थोड़े ही होता है ।

(क्रमशः)

टर्न–22 / हेमन्त / 06.02.2026

(क्रमशः)

श्री बाबुलाल शौर्य : कोई भी काम करो, तबीयत से करो। यही तो काम करना नीतीश कुमार जी की सरकार ने सिखाया है, काम करना सिखाया है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखिये।

श्री बाबुलाल शौर्य : चारी, लूट और अपहरण करना नहीं सिखाया है। क्या था 2005 से पहले, अपहरण एक बहुत बड़ा उद्योग था। यहां कर्म करना माननीय नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार ने सिखाया है। मित्रों, ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं आप। जाइए हॉस्पिटल, जितने हॉस्पिटल थे, वहां पर आंकड़ा

तो प्रस्तुत हुआ कि एक महीने में प्रखंड हॉस्पिटल में 39 मरीज जाते थे, आज 11,000 लोग मरीज जाते हैं दिखाने के लिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे न बोलें।

श्री बाबुलाल शौर्य : आखिर क्या कारण है? आखिर कारण क्या है ये बताओ? आप भी वहीं जाते हैं, आपके भी समर्थक, आपको भी मानने वाले, उसी सदर अस्पताल में जाते हैं, उसी प्रखंड अस्पताल में जाते हैं, और इलाज कराकर आते हैं और नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं। आप देखिए, सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के कारण ही बार–बार जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और विगत चुनाव में तो जनता सुनामी का आशीर्वाद दी है। उसके बल से ही आज हमारी सरकार पुनः एक कल्याणकारी और विकसित बिहार 2047 के विजन वाला बजट लेकर आई है। तेज गति से विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकताएं 2005 से ही तय हैं। वह सुशासन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, युवाओं के लिए रोजगार का, महिलाओं के सम्मान का, उसके स्वाभिमान का, बुजुर्गों की सुरक्षा, उनके देखभाल का। महिलाओं की बात करते हैं आप, क्या था 2005 से पहले ? घर में मां कहती थी कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? बच्चे स्कूल गए।

(व्यवधान)

अरे वही दिखा रहे हैं। आज घटना अगर कहीं घटती है तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अगर घटना घटी है, सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच के लिए....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति। बोलने दीजिए उनको। कृपया, बैठे–बैठे मत बोलिये।

श्री बाबुलाल शौर्य : आपसे, आप लोग के समय में केस...

अध्यक्ष : कृपया, बैठे–बैठे न बोलिये।

श्री बाबुलाल शौर्य : इसलिए हमारी सरकार ने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को दिया है। 68.216 करोड़ का बजट हम बिहार के नए मॉडल स्कूल, बेहतर शिक्षक,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति।

श्री बाबुलाल शौर्य : स्वास्थ्य के लिए संसाधन और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे बिहार का हर नौनिहाल, हर युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर विकसित बिहार के सपनों को पूरा करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए, हमारी उपलब्धि सर्वविदित है। पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इस विजन के साथ हमारी सरकार दिन–रात कार्य कर रही है। इसके साथ ही, इस बजट में आईजीआईएमएस में एक नए भवन का प्रावधान सुनिश्चित करते हुए यह संदेश दिया है कि हम गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी अपने ही राज्य में

करवाया जा सकेगा। अरे, आप लोग व्याकुल होते हैं, आप लोग व्याकुल हैं। व्याकुल मत होइए।....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति।

श्री बाबुलाल शौर्य : पहले का क्या था ? खेलोगे, कूदोगे, तो बनोगे खराब, पढ़ोगे–लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज तो माननीय नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने कहा है कि खेलोगे–कूदोगे, तो उससे बड़ा नवाब बनोगे और खेलने वालों को भी नौकरी देने का काम किया, यह है नीतीश सरकार। आप किस सेक्टर में देखिए? महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। आज देखिए, घर से महिलाएं निकलीं। आज देखिए न, महिलाएं सजग हो गईं।....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोलिये। मैडम, प्लीज।

श्री बाबुलाल शौर्य : महिलाओं में जो ताकत है, मां जानकी की धरती है, यह मां जानकी की धरती है। नीतीश कुमार ने मां जानकी को पहचान देने का काम किया है और इसलिए बिहार के, जहां मां परवरिश जिसकी करती हो, उसके बच्चे मजबूत होते हैं। इसलिए पूरे भारत को सींचने का काम बिहार के नौजवान करते हैं, क्योंकि माता का प्रभाव है, मां जानकी का प्रभाव है। राम के भी गुरु का यह क्षेत्र है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु का यह क्षेत्र है। इसलिए मैंने कहा, आप सीखिए। उस मां को कलंकित मत कीजिए, जिस मां ने आपको भी सींचा है, जिस मां ने हम सबको सींचा है। इसलिए हम यही कहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को ताकत देने का काम किया है, आधी आबादी के चक्कर में तो 25 पर आ गए। थोड़ा सा और मां को गरियाइयेगा, तो जीरो पर आउट हो जाइएगा, चिंता मत कीजिए। हम लोग यही कहेंगे, इतना ही कह कर अपनी अपनी वाणी को विराम देते हैं और परबत्ता की देव तुल्य जनता, त्रिवेणी उत्तर वाहिनी,...

(व्यवधान)

पर्यटन विभाग ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तभी तो लोग आ रहे हैं और मैं उत्तर वाहिनी,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैडम, कृपया बैठे–बैठे मत बोलिये। शांति, शांति।

श्री बाबुलाल शौर्य : मैं उत्तर वाहिनी, गंगा के उस तट से आया हूं जो मोक्ष दायिनी तट है, अगर पीड़ा हो तो मोक्ष के लिए जाइए त्रिवेणी गंगा धाम में, त्रिवेणी गंगा धाम अगवानी घाट में मोक्ष की डुबकी लगाइए, तो मोक्ष मिल जाएगा। इतना ही कह कर मैं वाणी को विराम देता हूं।

अध्यक्ष : शांति, शांति।

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श दिनांक 9 फरवरी, 2026 को भी जारी रहेगा। मैं एक बार पुनः कल के व्याख्यान कार्यक्रम बिहार विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर आपको याद दिला रहा हूं। कल 10.30 बजे के पहले आप सेंट्रल हॉल आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा, ओम बिरला जी आ रहे हैं, उपसभापति, राज्यसभा, हरिवंश जी आ रहे हैं और माननीय भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी आ रहे हैं। आप सबों से आग्रह है, कल के कार्यक्रम में आप अवश्य रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 6 फरवरी, 2026 के लिए, स्वीकृत निवेदनों की संख्या 41 है। अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 9 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।